मुंबई (महाराष्ट्र) से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

उत्तरशक्ति

हर खबर निष्पक्षता के साथ

मुंबई
वर्ष: 9 अंक 11
गुरुवार, 16 जुलाई 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

अमित शाह की उपस्थिति में एमसीडी और एनडीडीबी ने सीबीजी प्लांट्स की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली, 15 जुलाई। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने दिल्ली में गोबर के समुचित उपयोग के लिए कंप्रेस्ड बायो-गैस प्लांट्स की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, दिल्ली के उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केन्द्रीय गृह सचिव और केन्द्रीय सहकारिता सचिव सहित केन्द्र एवं दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हुआ समझौता देश के सभी बड़े शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए एक मॉडल का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से न सिर्फ पशु पालकों की आय बढ़ेगी, स्वच्छता भी बढ़ेगी, कंप्रेस्ड बायो-गैस प्राप्त होगी और ऑर्गेनिक खेती की दिशा में भी इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी।

अमित शाह ने कहा कि सभी देशवासी चाहते हैं कि यमुना नदी का जल स्वच्छ हो, लेकिन यह कल्पना यमुना नदी में गिरने वाली गंदगी के निकास के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यमुना जी के शुद्धिकरण के संकल्प की सिद्धि की दिशा में यह समझौता एक अहम कदम है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गटर के पानी और औद्योगिक कचरे के शुद्धिकरण के लिए दिल्ली में लगभग 80 ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में थोड़ा सा भी गोबर यमुना जी में न जा पाए, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि सवा लाख मवेशियों के अपशिष्ट के निस्तारण के बिना यह संभव नहीं होगा। शाह ने कहा कि दिसंबर, 2028 तक हम यह सुनिश्चित करेंगे कि एक भी लीटर गंदा पानी यमुना नदी में न जाए।

अमित शाह ने कहा कि नांगली, घोघा-गोयला और गाजीपुर अपशिष्ट निस्तारण प्लांट्स से गोबर की प्रोसेसिंग का काम पूरा होगा। उन्होंने कहा कि सभी शहरी क्षेत्रों की स्वच्छता और देशभर के करोड़ों पशुपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में यह प्रतीकात्मक पहल बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि आज हुआ यह समझौता देशभर के सभी महानगरों के लिए और बाद में गोबर प्रोसेसिंग के माध्यम से देशभर के ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते में प्रति किलो 1 पशुपालकों को देने का प्रावधान किया गया है।

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: दिल्ली, पंजाब समेत 4 राज्यों में वोटर लिस्ट की समय-सीमा बढ़ी

नई दिल्ली, 15 जुलाई। चुनाव आयोग ने दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना और कर्नाटक में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' के तहत गिनती की अवधि और अंतिम वोटर लिस्ट जारी करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली और कर्नाटक में, गिनती की अवधि 29 जुलाई से बढ़ाकर 8 अगस्त कर दी गई है। वोटर लिस्ट का ड्राफ़्ट अब 17 अगस्त को जारी किया जाएगा, जबकि पहले इसकी समय-सीमा 5 अगस्त थी। दावे और आपत्तियां 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकेंगी और फाइनल लिस्ट 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी, जो पहले तय तारीख 7 अक्टूबर से बारह दिन बाद है।

पंजाब में, बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा गिनती के लिए घर-घर जाकर जानकारी जुटाने की समय-सीमा 3 अगस्त तक बढ़ा दी गई है और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 13 अगस्त को जारी की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय 13 अगस्त से 12 सितंबर तक होगा और फाइनल वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर को जारी की जाएगी। तेलंगाना में, घर-घर जाकर वेरिफिकेशन का काम 3 अगस्त तक जारी रहेगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 10 अगस्त को जारी की जाएगी और 10 अगस्त से 9 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। फाइनल वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर को जारी की जाएगी। आयोग ने SIR प्रक्रिया में शामिल हर BLO और BLO सुपरवाइजर के लिए 6,000 रुपये के एकमुश्त विशेष मानदेय को भी मंजूरी दी है। चुनाव आयोग के एक पत्र में कहा गया है, मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रक्रिया में शामिल काम की मात्रा और प्रकृति को देखते हुए, आयोग ने इस प्रक्रिया में लगे हर BLO और BLO सुपरवाइजर को उनके सालाना वेतन के अलावा 6,000 रुपये का एकमुश्त मानदेय देने की मंजूरी दी है।

घर में समारोह दौरान अचानक गिर गई छत, 11 लोगों की मौत व कई घायल

पाकिस्तान, 15 जुलाई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी बारिश के कारण बड़ा हादसा हो गया। कोहाट जिले के लाची तहसील स्थित मलागिन इलाके में एक मकान की छत गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के समय घर में पारिवारिक समारोह चल रहा था। स्थानीय मीडिया के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब घर में परिवार के सदस्य एकत्रित थे। लगातार हो रही बारिश के कारण मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई और करीब 15 लोग मलबे के नीचे दब गए। सूचना मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सभी लोगों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 11 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है।

रेस्क्यू अधिकारियों के मुताबिक, घायलों और मृतकों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। मृतकों की पहचान बसमीना (50), नवाब जाना (45), फरमीना (45) और 6 वर्षीय अरहम सहित अन्य लोगों के रूप में हुई है। बता दें कि पाकिस्तान में मानसूनी बारिश लगातार तबाही मचा रही है। 2 जुलाई को पंजाब प्रांत में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 2 लोगों की मौत और 9 लोग घायल हुए थे। अटॉक में दीवार गिरने, शेखूपुरा में लकड़ी की छत ढहने और सरगोधा में साइनबोर्ड गिरने जैसी घटनाएं सामने आई थीं। 14 जून को खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत और 33 लोग घायल हुए थे। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान जर्जर इमारतों से दूर रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

उत्तर प्रदेश की विशाल युवा आबादी राज्य की सबसे बड़ी ताकत है, कोई चुनौती नहीं: योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, 15 जुलाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के युवाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बड़ी युवा आबादी कोई चुनौती नहीं, बल्कि राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार अब युवाओं को कौशल प्रदान कर इस जनसंख्या को आर्थिक विकास की एक बड़ी शक्ति में बदल रही है।

यूनेस्को की इस वर्ष की थीम 'साझा भविष्य के लिए कौशल' का जिक्र करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि इसका अर्थ सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा कार्यशक्ति है। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को कौशल से लैस कर इस जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग करेंगे और उन्हें समृद्धि के पथ पर आगे ले जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी (एसपी) पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले राज्य की शिक्षा व्यवस्था बदहाल थी और कौशल विकास का कोई प्रभावी तंत्र नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय असुरक्षा का माहौल था, जिसमें न महिलाएं सुरक्षित थीं और न ही व्यापारी। युवाओं के सामने पहचान का संकट था और उन्हें राज्य के बाहर भेदभाव का सामना करना पड़ता था क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर नहीं थे।

भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का नाम लिए बिना कहा कि सरकारी नौकरियों पर एक ही परिवार का कब्जा था। उन्होंने 'चाचा-भतीजे' की जोड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि भर्तियां निकलते ही वे पैसे वसूलने निकल पड़ते थे और बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता था।आदित्यनाथ ने इस बात पर दुख जताया कि उपजाऊ जमीन, प्रचुर जल संसाधन और समृद्ध धार्मिक विरासत के बावजूद उत्तर प्रदेश को लंबे समय तक 'बीमारू' राज्य कहा गया। उन्होंने गंगा, यमुना, सरयू जैसी नदियों और अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे महान धार्मिक स्थलों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के बीमारू बने रहने का कारण यहां के लोग नहीं, बल्कि पिछली सरकारों की नकारात्मक सोच थी।मुख्यमंत्री ने 2017 के बाद अपनी सरकार की उपलब्धियों का विवरण देते हुए लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की स्थापना की चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए सरकार ने विरोध के बावजूद 200 एकड़ जमीन मुफ्त दी, जिससे लगभग 500 आईटीआई और इंजीनियरिंग छात्रों को रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण ही आज राज्य के युवाओं को अवसर मिल रहे हैं और ब्रह्मोस की बिक्री से सरकार को करीब 65 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व भी प्राप्त हुआ है।

मोदी कैबिनेट ने ले लिये बड़े फैसले, किसानों और नौजवानों को दे डाली बड़ी सौगात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में देश की विनिर्माण क्षमता, बुनियादी ढांचे, कृषि, परिवहन और समुद्री क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इन निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम और वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासीहम आपको बता दें कि कैबिनेट ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (एमपीएमएस) को 62,500 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहने वाली इस योजना के तहत भारत में मोबाइल फोन निर्माण पर 2.25 से 5 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। घरेलू स्तर पर प्रमुख कंपोनेंट्स की खरीद पर अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत और भारतीय ब्रांडों द्वारा डिजाइन एवं अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि योजना अवधि में लगभग 39 लाख करोड़ रुपये का मोबाइल उत्पादन होगा, निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा करीब 60 हजार प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। यह योजना पीएलआई योजना के बाद भारत को वैश्विक मोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में और मजबूत करेगी।

साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को और गति देने के लिए सरकार ने सेमिकॉन 2.0 को भी 1.27 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ मंजूरी दी। यह कार्यक्रम चिप डिजाइन, मशीनों एवं कच्चे माल के निर्माण, नए फैब स्थापित करने, एटीएमपी/ओसैट इकाइयों के विस्तार, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रतिभा विकास जैसे छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगा।

ममता बनर्जी का बीजेपी पर तीखा प्रहार

कोलकता, 15 जुलाई। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्हें एक और झटका तब लगा जब विधायक मदन मित्रा बागी खेमे में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, जो जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं और साथ ही कहा कि उनके पास बीजेपी के लिए एक संदेश है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी चाहती थी कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। ममता ने कहा कि बीजेपी चाहती थी कि मुझे हार्ट अटैक आए, लेकिन मैं तब तक ज़िंदा रहूँगी जब तक आपका अंत न देख लूँ। बुधवार को मित्रा ने ममता का खेमा छोड़कर रिताब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ.विधानसभा में अपना कमरा बदला है। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के छह महीने के लिए पद से हटने की उनकी मांग न माने जाने के बाद उन्होंने TMC छोड़ दी।

उनके इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता ने कहा कि मित्रा ने इसलिए पद छोड़ा क्योंकि एऊ ने मंगलवार को उनकी पत्नी और दो बेटों को समन भेजा था। उन्होंने यह भी कहा कि अभिषेक बनर्जी का उनके इस फैसले से कोई लेना-देना नहीं था। ममता ने कहा कि अभिषेक पार्टी पर हमलों के लिए एक बहाना बन गए हैं, जबकि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को बार-बार समन भेजे गए हैं। उन्होंने समझौते के जरिए राहत पाने के बजाय राजनीतिक लड़ाई जारी रखने के लिए उनकी तारीफ की।

बुधवार को फेसबुक लाइव के दौरान TMC प्रमुख ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को एक बहाना बना दिया गया है। उनके परिवार के सदस्यों को समन भेजे गए थे। अगर वह चाहते तो राहत पा सकते थे। लेकिन वह लड़ाई के मैदान से पीछे नहीं हटे। जिस तरह से उन्होंने लड़ना जारी रखा है, उनकी सभी कमियों को माफ कर दिया गया है। पार्टी छोड़ने वालों की आलोचना करते हुए ममता ने कहा कि मैं इन गद्दारों की ओर से जनता से माफी मांगती हूँ।

TIWARI'S
SARASWATI CLASSES
Since 1992
Parents' First Choice for 34+ Years
Prof. Dr. Dayanand Tiwari
Founder & Academic Director
ADMISSIONS OPEN
9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE
NEET | JEE | MHT-CET
10 DAYS FREE DEMO
Attend Classes • Experience Our Teaching
Take Admission After Satisfaction
(No Hidden Conditions)
- 34+ Years of Academic Excellence
- Experienced & Dedicated Faculty
- Personal Attention
- Printed Notes & Regular Tests
- Strong Foundation for Boards & Competitive Exams

Santacruz Branch
101 Sai Chambers, Opp. Santacruz Railway Station (East), Near Depot, Santacruz (E), Mumbai-400055

Sion Branch
Opp. SIES College (Old), Near Gurukripa Hotel, Sion (West), Mumbai

Limited Seats / Small Batch Size
CALL NOW:
7738007373

DAKS REHAB CENTRE
(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)
Contact us: 9820519851
विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीबी नगर मुंबई-37

- Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
- बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
- वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
- DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
- NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
- चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
- एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
- पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
- मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
- विशेषज्ञ डॉक्टरो से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
- मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तीयों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध

NEW LIGHT CLASSES
TRADITION OF EXCELLENCE
2nd Floor, Sheetal Bldg. Near Diamond Talkies, L. T. Road, Borivali (West) Mumbai - 400 092 Maharashtra
ADMISSIONS OPEN
ALL OVER INDIA
ENROLL NOW

SMART CLASSROOM
(ONLINE/OFFLINE)
Courses Offered
- Std. XI & XII (Sci.)
- NEET
- JEE (Main & Advance)
- MHT-CET
- Polytechnic & Engg
- Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)

M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

जगन्नाथ महायात्रा– 16 जुलाई, 2026
आस्था, परम्परा, आध्यात्मिक चेतना का विराट उत्सव

-ललित गर्ग

आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से प्रारम्भ होकर दस दिनों तक चलने वाली भगवान श्री जगन्नाथ की रथयात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, लोकआस्था, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक दर्शन का विराट उत्सव है। पुरी की यह महायात्रा हजारों वर्षों की परम्परा का जीवंत प्रतीक है, जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। इसी कारण इसे ह्यमहायात्राह्ल कहा जाता है। भारत के चार धामों में प्रतिष्ठित श्री जगन्नाथ धाम की यह यात्रा देश ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व के करोड़ों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र बनती है। वर्ष 2026 की रथयात्रा भी अपार श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई जा रही है, किन्तु इस बार इसके साथ एक नया विवाद भी जुड़ गया है। देश एवं विदेश के अनेक स्थानों पर इस्कॉन द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग तिथियों पर रथयात्राएं आयोजित किए जाने पर कुछ धार्मिक एवं परम्परावादी संगठनों ने आपत्ति व्यक्त की है। उनका मत है कि जगन्नाथ रथयात्रा की तिथि वही होनी चाहिए जो पुरी श्रीमंदिर द्वारा निर्धारित होती है। दूसरी ओर इस्कॉन का तर्क है कि विदेशों में स्थानीय प्रशासन की अनुमति, सार्वजनिक अवकाश, मौसम तथा अन्य व्यावहारिक कारणों से कभी-कभी तिथि में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। यह विवाद केवल तिथि का नहीं, बल्कि परम्परा और वैश्विक विस्तार के बीच संतुलन खोजने का विषय बन गया है।

वास्तव में यह समझना आवश्यक है कि पुरी की रथयात्रा और अन्य स्थानों पर आयोजित रथयात्राओं का स्वरूप अलग-अलग हो सकता है, किन्तु उनका मूल उद्देश्य भगवान जगन्नाथ की भक्ति, लोककल्याण और धर्मप्रचार ही है। यदि परम्परा का सम्मान बना रहे और श्रद्धा अक्षुण्ण रहे तो मतभेद संवाद के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। धर्म का मूल स्वरूप जोड़ना है, विभाजन करना नहीं। पुरी का श्रीमंदिर भगवान जगन्नाथ का मुख्य धाम है। लगभग 800 वर्ष पुराने इस मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण जगन्नाथ स्वरूप में अपने बड़े भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। प्रतिवर्ष केवल एक बार तीनों देव विग्रह अपने गर्भगृह से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है। सामान्य दिनों में जहां भगवान के दर्शन सीमित होते हैं, वहीं रथयात्रा में प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के भगवान के साक्षात दर्शन कर सकता है।

यात्रा की तैयारियां अक्षय तृतीया से प्रारम्भ हो जाती हैं। उसी दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के तीनों विशाल रथों का निर्माण आरम्भ होता है। प्रत्येक वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। यद्यपि उनका स्वरूप और आकार सदियों से समान रहता है, फिर भी प्रत्येक वर्ष नई लकड़ी, नई सज्जा और नवीन निर्माण किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ गरुड़ध्वज (कपिलध्वज), बलभद्र का तालध्वज तथा सुभद्रा का दर्पदलन अथवा पद्मध्वज कहलाता है। इन रथों के निर्माण की प्रक्रिया केवल शिल्पकला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना मानी जाती है। कारीगर विशेष धार्मिक नियमों का पालन करते हुए इन्हें बनाते हैं। यह परम्परा हमें यह संदेश देती है कि प्रत्येक वर्ष मनुष्य भी अपने भीतर की ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और लोभ को त्यागकर स्वयं का नव-निर्माण करे।

रथयात्रा के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि एक बार सुभद्रा ने द्वारका नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्रीकृष्ण और बलराम ने उन्हें अलग रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया। उसी स्मृति में तीनों भाई-बहनों की संयुक्त रथयात्रा निकाली जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान की अपूर्ण प्रतिमाओं का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था, जो आज भी जगन्नाथ संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इस महायात्रा का एक अत्यन्त मार्मिक पक्ष यह भी है कि स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान अस्वस्थ माने जाते हैं और लगभग पन्द्रह दिनों तक सार्वजनिक दर्शन नहीं देते। इसके पश्चात वे रथों पर आरूढ़ होकर अपनी मौसी के घर गुण्डिचा मंदिर जाते हैं। वहां नौ दिनों तक विश्राम करते हैं और फिर बहुड़ा यात्रा के माध्यम से पुनः श्रीमंदिर लौटते हैं। लौटते समय भगवान का पोडा पीठा ग्रहण करना, पंचमी को देवी लक्ष्मी का रुष्ट होकर रथ का पहिया तोड़ना तथा बाद में भगवान द्वारा उन्हें मनाने की परम्परा भक्तिभाव एवं मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है।

पुरी की रथयात्रा का एक अन्य अद्भुत दृश्य छेरा पहरा है। गजपति महाराज स्वयं स्वर्ण निर्मित झाड़ू से रथों के मार्ग की सफाई करते हैं। यह परम्परा संदेश देती है कि ईश्वर के समक्ष राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं। सत्ता का सर्वोच्च पद भी सेवा से बड़ा नहीं हो सकता। रथयात्रा के समय जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद भी विशेष आकर्षण का केन्द्र होता है। विश्व की सबसे बड़ी मंदिर रसोइयों में से एक इस रसोई में मिट्टी के पात्रों में प्रसाद बनाया जाता है। दाल, चावल, सब्जियाँ, मालपुआ, गजामूंग, लाई, नारियल तथा अनेक प्रकार के व्यंजन अत्यंत अल्प मूल्य पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि समानता और साझेदारी का प्रतीक है।

धार्मिक ग्रन्थों में रथयात्रा का अत्यन्त महत्व बताया गया है। स्कन्द पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण तथा उत्कल खण्ड में भगवान जगन्नाथ की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। मान्यता है कि रथयात्रा के दर्शन एवं रथ को स्पर्श करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं तथा रथ खींचने वाले को मोक्ष का अधिकारी माना गया है। यद्यपि इन मान्यताओं का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन-रथ को धर्म, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलाता है, वही वास्तविक मुक्ति प्राप्त करता है। जगन्नाथ रथयात्रा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सामाजिक समरसता है। इस अवसर पर जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र अथवा सम्प्रदाय का कोई भेद नहीं रहता। लाखों श्रद्धालु एक साथ रथ की रस्सी खींचते हैं। यही वह क्षण होता है जब धर्म केवल पूजा-पद्धति न रहकर सामाजिक एकता का उत्सव बन जाता है।

आज यह यात्रा केवल पुरी तक सीमित नहीं रही। भारत के लगभग सभी प्रमुख नगरों सहित अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और अनेक यूरोपीय देशों में भी जगन्नाथ रथयात्रा आयोजित होती है। विशेष रूप से इस्कॉन ने इस परम्परा को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करोड़ों विदेशी भक्तों ने इसी माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण एवं जगन्नाथ संस्कृति को जाना है। इसलिए यदि कहीं तिथियों को लेकर व्यावहारिक परिवर्तन भी किए जाएँ तो उनके पीछे धार्मिक अवमानना नहीं, बल्कि स्थानीय व्यवस्थाओं की विवशता भी हो सकती है। फिर भी यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि जहाँ तक सम्भव हो, श्रीमंदिर की परम्परा और निर्धारित तिथि का सम्मान किया जाए, ताकि सम्पूर्ण विश्व में एकात्मता का संदेश और अधिक सुदृढ़ हो।

दार्शनिक दृष्टि से रथ मनुष्य के शरीर का, भगवान आत्मा का तथा रथ को खींचने वाली रस्सियाँ समाज और लोकशक्ति का प्रतीक हैं। आत्मा तभी सार्थक होती है जब समाज सहयोग करे और समाज तभी श्रेष्ठ बनता है जब उसके केन्द्र में ईश्वर, नैतिकता और आत्मशुद्धि का भाव हो। यही कारण है कि जगन्नाथ रथयात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मविशुद्धि, लोकमंगल, समरसता, सेवा और आध्यात्मिक जागरण का अनुपम पर्व है। वर्तमान समय में जब समाज अनेक प्रकार के वैचारिक, सामाजिक और धार्मिक विभाजनों से गुजर रहा है, तब भगवान जगन्नाथ की यह महायात्रा हमें स्मरण कराती है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य विवाद नहीं, बल्कि संवाद है। वर्चस्व नहीं, बल्कि समन्वय है और बाहरी आडम्बर नहीं, बल्कि अंतःकरण की पवित्रता है। यही इस महायात्रा का सनातन संदेश है कि जीवन का रथ तभी सही दिशा में चलता है जब उसमें श्रद्धा, सेवा, समरसता, आत्मसंयम और लोककल्याण के पहिए समान गति से चलते रहें। यही जगन्नाथ महायात्रा की शाश्वत महिमा है और यही इसकी वैश्विक प्रासंगिकता।

आज पाकिस्तान इतिहास के सबसे खतरनाक और अंधकारमय मोड़ पर खड़ा है!

अशोक भाटिया

आज पाकिस्तान इतिहास के उस सबसे खतरनाक और अंधकारमय मोड़ पर खड़ा है, जहां से वापसी का हर रास्ता बंद दिखाई देता है। वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के अलग होने के बाद, इस्लामाबाद के सैन्य और असैन्य नेतृत्व ने इतिहास की उस भीषण त्रासदी से कोई सबक नहीं सीखा। वर्तमान में सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और आंतरिक संप्रभुता के मोर्चों पर जैसी बहुआयामी चुनौतियां एक साथ खड़ी हैं, वे यह गंभीर सवाल पैदा करती हैं कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर टुकड़े-टुकड़े होने की कगार पर आ पहुंचा है? यह संकट केवल राजनीतिक अस्थिरता या कुछ दलों की आपसी खींचतान का नहीं है, बल्कि यह आधुनिक इतिहास में किसी राज्य (StÔte) के बुनियादी ढांचे और उसकी वैचारिक नींव के पूरी तरह ढह जाने का सबसे जीवंत उदाहरण है। पाकिस्तान की स्थापना जिस 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांत' के आधार पर हुई थी, वह 1971 में ही दम तोड़ चुका था, लेकिन आज जो स्थिति है वह उससे भी कहीं अधिक भयावह है। आज संकट केवल एक हिस्से के अलग होने का नहीं, बल्कि पूरे देश के एक गृहयुद्ध की आग में झुलसकर कई स्वायत्त, हिंसक और अनियंत्रित गुटों में बंट जाने का है। जब किसी देश की सेना, न्यायपालिका, संसद और नागरिक समाज एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े हो जाएं, तो उस राष्ट्र के मानचित्र को बदलने से कोई बाहरी ताकत नहीं रोक सकती।

किसी भी संप्रभु राष्ट्र की रीढ़ उसकी अर्थव्यवस्था होती है, और पाकिस्तान की यह रीढ़ इस समय पूरी तरह टूट चुकी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बार-बार मिलने वाले 'बेलआउट पैकेज' भी देश की डूबती नैया को पार लगाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। वर्तमान में पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज लगभग $290 अरब तक पहुंच चुका है, जो उसकी सकल घरेलू उत्पाद का 70 प्रतिशत से अधिक है। इस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए पाकिस्तान को नया कर्ज लेना पड़ रहा है, जो उसे एक कभी न खत्म होने वाले 'डेथ ट्रैप' में धकेल चुका है।

देश के भीतर आर्थिक हालात यह हैं कि बढ़ती महंगाई ने आम नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी के कारण जरूरी दवाओं, कच्चे माल और पेट्रोलियम पदार्थों का आयात ठप हो चुका है। ईंधन और बिजली की अभूतपूर्व किल्लत के कारण सरकार को चार दिन का कार्य सप्ताह लागू करने, बाजारों को शाम होते ही बंद करने और स्कूलों को बंद रखने जैसे आपातकालीन उपाय करने पड़े हैं।

जब कोई परमाणु संपन्न देश बुनियादी ऊर्जा, आटा और जीवन रक्षक दवाओं के लिए दुनिया के सामने कटोरा फैलाने को मजबूर हो जाए, तो उसकी संप्रभुता केवल कागजों तक सीमित रह जाती है। विश्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं की कड़ी शर्तों ने पाकिस्तान के आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जिससे जनता का अपनी सरकार और राज्य व्यवस्था पर से विश्वास पूरी तरह उठ चुका है। यह आर्थिक पतन ही है जो बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांतों में अलगाववाद की आग में घी डालने का काम कर रहा है।

सैन्य और रणनीतिक मोर्चे पर, पाकिस्तान अपनी ही भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक भीषण, अदृश्य और बहुआयामी युद्ध लड़ रहा है। बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी आंदोलन अब महज एक असंतोष नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक संगठित गुरिल्ला युद्ध में बदल चुका है। बलूच लिबरेशन आर्मी और माजिद ब्रिगेड जैसे संगठनों ने अपनी रणनीति बदलते हुए छिटपुट हमलों की जगह पाकिस्तानी सेना के कोर मुख्यालयों और रणनीतिक ठिकानों पर सीधे और समन्वित हमले शुरू कर दिए हैं। हाल ही में सेना के ऑपरेशन शबान के खिलाफ बलूच विद्रोहियों की हिंसक प्रतिक्रिया ने यह साबित कर दिया है कि बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से पर इस्लामाबाद का प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो चुका है और वहां सेना केवल अपनी चौकियां बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। दूसरी तरफ, उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थिति और भी बदतर है। डूरंड रेखा के पार से संचालित होने वाले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई जिलों में अपनी समानांतर सरकार स्थापित कर ली है। टीटीपी के लड़ाके अत्याधुनिक अमेरिकी हथियारों से लैस हैं, जो उन्हें अफगानिस्तान में मिले थे। वे पाकिस्तानी पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर रोजाना आत्मघाती हमले कर रहे हैं।

इस परिदृश्य का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अब वैचारिक रूप से भिन्न होने के बावजूद बलूच अलगाववादी (जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की बात करते हैं) और टीटीपी जैसे धार्मिक कट्टरपंथी संगठन पाकिस्तानी राज्य व्यवस्था के खिलाफ एक साझा मोर्चा बना रहे हैं। ये संगठन न केवल सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की अरबों डॉलर की परियोजनाओं और चीनी इंजीनियरों पर लगातार हमले कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप चीन ने भी अब पाकिस्तान की सुरक्षा क्षमता पर भरोसा खो दिया है और वह अपनी संपत्तियों की रक्षा के लिए अपनी निजी सुरक्षा एजेंसियों या सेना को पाकिस्तान में तैनात करने का दबाव बना रहा है, जो पाकिस्तान की संप्रभुता के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है।

पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार देखा जा रहा है कि वह एक साथ तीन सक्रिय और बेहद संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर गंभीर सुरक्षा और कूटनीतिक संकट का सामना कर रहा है। १ ,कभी जिसे पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व अपनी 'रणनीतिक गहराई' और सुरक्षित पिछवाड़ा समझता था, आज वही अफगानिस्तान उसका सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन चुका है। काबुल में तालिबान सरकार के आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसकी पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन इसके विपरीत डूरंड रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद हिंसक झड़पों में बदल चुका है। सीमा पार से होने वाले हमलों और पाकिस्तान द्वारा की गई हवाई कार्रवाइयों ने दोनों देशों को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। 2 दक्षिण-पश्चिम में ईरान के साथ सीमा भी अब सुरक्षित नहीं रही है। दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में हुए मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाइयों ने अविश्वास की एक ऐसी गहरी खाई खोद दी है, जिसे पाटना नामुमकिन लग रहा है। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान अपनी धरती पर जैश-अल-अदल जैसे सुन्नी आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है, जबकि पाकिस्तान बलूच विद्रोहियों को ईरान में शरण मिलने का दावा करता है। इस तनाव के कारण पाकिस्तान को अपनी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सीमा पर तैनात करना पड़ा है, जिससे उसके आर्थिक संसाधन और समाप्त हो रहे हैं।३ पूर्व में भारत ने अपनी पारंपरिक रक्षात्मक नीति को पूरी तरह बदलते हुए साफ कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ 'सक्रिय और आक्रामक कार्रवाई' से पीछे नहीं हटेगा। कश्मीर में धारा 370 के हटने और भारत की बढ़ती वैश्विक धक के बाद पाकिस्तान कूटनीतिक रूप से बिल्कुल अलग-थलग पड़ चुका है। इस तीन तरफा घिराव ने पाकिस्तानी सेना के संसाधनों, मनोबल और उसकी सामरिक क्षमता को पूरी तरह निचोड़ कर रख दिया है।

पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण वाले कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान में स्थिति अब नियंत्रण से बाहर और अत्यधिक विस्फोटक हो चुकी है। दशकों से जारी आर्थिक उपेक्षा, भारी करों के बोझ, आटे-बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की किल्लत और मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ स्थानीय जनता ने एक निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जैसे नागरिक संगठनों के नेतृत्व में लाखों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं।

दिलचस्प और ऐतिहासिक बदलाव यह है कि अब ये प्रदर्शनकारी केवल स्थानीय स्वायत्तता या सब्सिडी की मांग नहीं कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक की सड़कों पर खुलकर पाकिस्तान से आजादी और भारत के साथ विलय के नारे गूंज रहे हैं। वहां की जनता सार्वजनिक रूप से पाकिस्तानी झंडे जला रही है और पाकिस्तानी सेना को एक 'कब्जाधारी और लुटेरी फौज' के रूप में संबोधित कर रही है। जब किसी देश की जनता अपनी ही रक्षक होने का दावा करने वाली सेना के खिलाफ इस हद तक बागी हो जाए, तो उस क्षेत्र को बंदूकों के दम पर बहुत लंबे समय तक भौगोलिक रूप से बांधकर रखना मुमकिन नहीं होता। गिलगित-बाल्टिस्तान में भी लद्दाख के साथ ऐतिहासिक व्यापारिक रास्तों को खोलने की मांग गति पकड़ रही है, जो इस्लामाबाद के लिए एक बड़ा भू-राजनीतिक झटका है।

इस विनाशकारी और निराशाजनक परिदृश्य के बीच, दुनिया के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह उठता है कि क्या पाकिस्तान का औपचारिक रूप से सोवियत संघ या यूगोस्लाविया की तरह बिखर जाना तय है? अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और भू-राजनीति के कई वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि हालात बेहद खराब होने के बावजूद, देश का तत्काल और कानूनी रूप से कई टुकड़ों में टूट जाना इतना आसान नहीं है। इसके पीछे दो मुख्य अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक कारण काम कर रहे हैंः पहला वैश्विक समुदाय, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और यहां तक कि चीन भी कभी नहीं चाहेगा कि 24 करोड़ की आबादी वाला और परमाणु हथियारों से लैस कोई देश पूरी तरह अराजकता में बिखर जाए। यदि पाकिस्तान एक राज्य के रूप में पूरी तरह विफल होकर टूटता है, तो उसके सैकड़ों परमाणु हथियारों और मिसाइल तकनीक के विभिन्न आतंकवादी संगठनों, गैर-राज्य तत्वों या धार्मिक चरमपंथियों के हाथ में जाने का सीधा खतरा पैदा हो जाएगा। यह परिदृश्य पूरी दुनिया के अस्तित्व के लिए एक दुःस्वप्न जैसा होगा। इसलिए, अंतरराष्ट्रीय ताकतें अपनी रणनीतिक मजबूरियों के कारण पाकिस्तान को 'डूबने' तो दे रही हैं, लेकिन उसे पूरी तरह 'मरने' या बिखरने से बचाने के लिए समय-समय पर वित्तीय ऑक्सीजन देती रहती हैं।दूसरा - पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी भले ही रणनीतिक रूप से कमजोर और जनता की नजरों में बदनाम हो चुकी हों, लेकिन देश के आंतरिक संसाधनों, न्यायपालिका, मीडिया और राजनीतिक दलों पर आज भी उनका क्रूर नियंत्रण कायम है। सेना के पास अपनी सीमाओं को जबरन एकजुट रखने के लिए आधुनिक हथियार और क्रूर बल प्रयोग की असीमित क्षमता है। वे किसी भी बड़े विद्रोह को कुचलने के लिए मानव अधिकारों के हनन की सारी हदें पार करने को तैयार रहते हैं, जैसा कि वे बलूचिस्तान और सिंध में 'इन्फोर्सड डिसअपीयरेंस' के जरिए दशकों से करते आ रहे हैं।

ताजमहल के साये में दफ्न है इतिहास का कौन-सा सच?

-सुरेश गांधी

ताजमहल... दुनिया के सात अजूबों में शामिल वह इमारत, जिसे करोड़ों लोग प्रेम का प्रतीक मानते हैं। लेकिन भारत में ताजमहल केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि समय-समय पर उठने वाली ऐतिहासिक बहसों का भी केंद्र रहा है। कभी इसके बंद कमरों पर सवाल उठते हैं, कभी इसकी नींव पर, तो कभी इसके निर्माण से पहले वहाँ क्या था इस पर। इन तमाम बहसों के बीच एक दस्तावेज बार-बार सामने आता है 1896 में प्रकाशित सैयद मुहम्मद लतीफ की पुस्तक आगरा : हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का पृष्ठ 105। हाल के दिनों में वायरल इंटरव्यू और टीवी बहसों में भी इसी पृष्ठ का उल्लेख किया जा रहा है। आखिर इस पृष्ठ पर ऐसा क्या लिखा है, जिसने वर्षों से विवाद को जीवित रखा है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा, हम वर्षों से यही कह रहे हैं कि इतिहास से जुड़े इस विवाद को भावनाओं से नहीं, बल्कि मूल दस्तावेजों के आधार पर देखा जाना चाहिए। हमने अपने पक्ष में बादशाहनामा सहित कई ऐतिहासिक स्रोतों का उल्लेख किया है। विशेष रूप से आगरा : हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव के पृष्ठ 105 में बादशाहनामा के हवाले से यह उल्लेख मिलता है कि जिस स्थान पर आज ताजमहल है, वह राजा मानसिंह का महल था, जो उस समय राजा जय सिंह के अधिकार में था। हमारा कहना है कि इन ऐतिहासिक संदर्भों की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए, ताकि तथ्य देश के सामने आ सकें। लोकप्रिय विमर्श में अक्सर सीधे ‘मंदिर बनाम मकबरा’ की बहस शुरू हो जाती है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज पहले एक अलग प्रश्न उठाते हैं जिस भूमि पर ताजमहल बना, वह किसकी थी? यही वह बिंदु है, जहाँ इतिहास अपेक्षाकृत स्पष्ट दिखाई देता है। लतीफ अपनी पुस्तक में बादशाहनामा का हवाला देते हुए लिखते हैं कि मुमताज महल के मकबरे के लिए चुना गया स्थान मूलतः राजा मानसिंह के महल से जुड़ा था, जो उस समय उनके पौत्र राजा जय सिंह की संपत्ति था। साथ ही उल्लेख है कि शाहजहाँ ने इसके बदले जय सिंह को दूसरी संपत्तियाँ प्रदान कीं। यही पंक्तियाँ आज भी बहस का आधार बनती हैं। यानी पहला निष्कर्ष यह निकलता है कि भूमि और उससे जुड़ी संपत्ति का संबंध आमेर (जयपुर) के राजघराने से था। लेकिन यहीं से शुरू होता है दूसरा सवाल... अगर यह भूमि और महल जय सिंह की संपत्ति थे, तो फिर उस स्थान का आगे क्या हुआ? क्या पुरानी इमारत हटाई गई? क्या उसी का रूपांतरण हुआ? या पूरी तरह नया निर्माण हुआ? यहीं से इतिहास दो धाराओं में बँट जाता है।

मुख्यधारा के इतिहासकारों का मत है कि मुगलकाल में नदी किनारे बनी राजसी हवेलियों और बागों का अधिग्रहण कर उन्हें नए शाही निमार्णों में बदलना असामान्य नहीं था। उनके अनुसार उपलब्ध मुगलकालीन अभिलेख, स्थापत्य शैली और अन्य ऐतिहासिक स्रोत ताजमहल को शाहजहाँ द्वारा निर्मित मकबरे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) भी विभिन्न मामलों में यही रुख अपनाता रहा है कि उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य ताजमहल को मुगलकालीन स्मारक मानते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है फिर विवाद क्यों? यही वह प्रश्न है जो आज भी लाखों लोगों के मन में है। कुछ शोधकर्ता और याचिकाकर्ता कहते हैं कि यदि दस्तावेज में ‘राजा मानसिंह का महल’ लिखा है, तो उस महल का इतिहास विस्तार से सामने आना चाहिए। वे मानते हैं कि इस विषय पर और शोध तथा दस्तावेजों की समीक्षा होनी चाहिए।

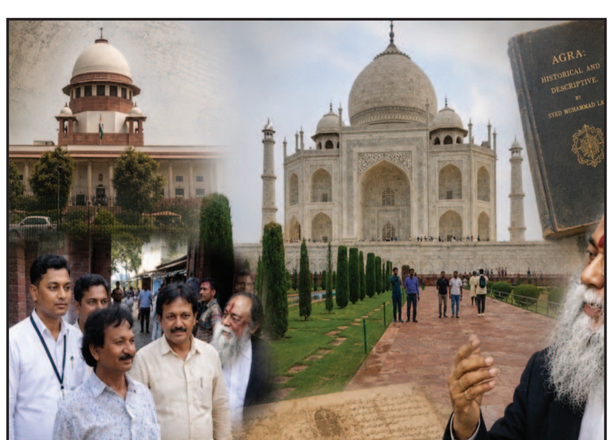

इतिहास कभी मरता नहीं। वह समय की धूल के नीचे दब जरूर जाता है, लेकिन जैसे ही कोई पुराना दस्तावेज खुलता है, कोई भूला हुआ संदर्भ सामने आता है या कोई नया सवाल उठता है, इतिहास फिर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। ताजमहल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दुनिया इसे प्रेम का सबसे अनुपम स्मारक मानती है, लेकिन भारत में इसकी पहचान केवल संगमरमर की खूबसूरती तक सीमित नहीं रही। यह इमारत दशकों से इतिहास, आस्था, पुरातत्व और राजनीति के चौराहे पर खड़ी है। कभी इसके बंद कमरों पर सवाल उठते हैं, कभी इसकी नींव पर, तो कभी उस जमीन पर, जहाँ यह खड़ा है। हाल के दिनों में एक बार फिर कुछ पुराने दस्तावेज, एक पुस्तक का चर्चित पृष्ठ और ऐतिहासिक संदर्भ राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बने हैं। सवाल नए नहीं हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल रहा है। यह रिपोर्ट किसी निष्कर्ष से शुरूआत नहीं करती। यह किसी पक्ष की पैरवी भी नहीं करती। यह सिर्फ उन दस्तावेजों के दरवाजे खोलती है, जिनका हवाला वर्षों से दिया जाता रहा है। इस श्रृंखला का उद्देश्य फैसला सुनाना नहीं, बल्कि पाठक को उस मुकाम तक ले जाना है, जहाँ इतिहास, दस्तावेज और दावे आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं। आगे का निर्णय पाठक स्वयं करे

दूसरी ओर इतिहासकार कहते हैं कि किसी स्थान पर पहले महल या हवेली होने का उल्लेख अपने-आप यह सिद्ध नहीं करता कि वह किसी विशेष धार्मिक स्थल का रूप था। ऐसे निष्कर्ष के लिए स्वतंत्र और निर्णायक पुरातात्विक साक्ष्य आवश्यक होंगे।

इस पूरी बहस में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दावा और दस्तावेज एक ही चीज नहीं होते। दस्तावेज यह बताते हैं कि भूमि का संबंध जय सिंह की संपत्ति से था। दावा यह कहता है कि वहाँ पहले क्या था। उपलब्ध ऐतिहासिक संदर्भों में राजा जय सिंह की संपत्ति का उल्लेख मिलता है। भूमि के बदले दूसरी संपत्ति दिए जाने का उल्लेख भी मिलता है। लेकिन उस आधार पर आगे के सभी दावों को स्वतः स्थापित ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जा सकता। उन पर आज भी शोध, बहस और अलग-अलग व्याख्याएँ मौजूद हैं। ताजमहल की कहानी भी शायद यहीं से शुरू होती है एक जमीन से, एक दस्तावेज से और उन सवालों से, जिनके जवाब खोजने की कोशिश आज भी जारी है। वैसे भी भारत में शायद ही कोई ऐसा स्मारक हो, जिसके इतिहास पर ताजमहल जितनी बहस हुई हो। एक ओर इसे प्रेम का सबसे भव्य प्रतीक कहा जाता है, दूसरी ओर समय-समय पर यह दावा भी उठता है कि यह स्मारक किसी पूर्ववर्ती हिंदू स्थापत्य पर आधारित है। इन दावों का सबसे अधिक उल्लेख हाल के वर्षों में न्यायालयों, सार्वजनिक विमर्श और टीवी बहसों में देखने को मिला है। क्या सचमुच राजा जय सिंह की थी यह जमीन? इस प्रश्न का उत्तर कई इतिहासकार 'हाँ' में देते हैं लेकिन उसके साथ एक महत्वपूर्ण संदर्भ भी जोड़ते हैं। मुगलकालीन इतिहास 'बादशाहनामा' का हवाला देते हुए 1896 में प्रकाशित सैयद मुहम्मद लतीफ की पुस्तक आगरा : हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में उल्लेख मिलता है कि मुमताज महल के मकबरे के लिए चुना गया स्थान मूलतः राजा मानसिंह के महल से जुड़ा था, जो उस समय उनके पौत्र राजा जय सिंह की संपत्ति था। पुस्तक के पृष्ठ 105 का यही उल्लेख आज भी बहस का केंद्र बना हुआ है। यहीं से पहला तथ्य सामने आता है भूमि और उससे जुड़ी संपत्ति का संबंध जयपुर राजघराने से था। यहीं से शुरू होता है दूसरा सवाल यदि यह स्थान जय सिंह की संपत्ति था, तो वहाँ पहले क्या था? यही वह बिंदु है जहाँ इतिहास और विवाद एक-दूसरे से टकराते हैं। कुछ शोधकर्ता और याचिकाकर्ता कहते हैं कि इस प्रश्न की गहन पुनर्पड़ताल होनी चाहिए। उनका तर्क है कि उपलब्ध दस्तावेजों की नई दृष्टि से समीक्षा आवश्यक है। दूसरी ओर, अधिकांश पेशेवर इतिहासकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मत है कि उपलब्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य ताजमहल को शाहजहाँ के काल में निर्मित मकबरे के रूप में ही समर्थन देते हैं।

'महल' और 'जमीन'–बहस का असली मोड़

इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प तथ्य सामने आता है। कुछ लेखकों ने यह प्रश्न उठाया कि बाद के कुछ विवरणों में ‘राजा मानसिंह का महल’ की जगह ‘राजा मानसिंह की जमीन’ जैसा उल्लेख क्यों मिलता है। इसी अंतर को लेकर कई वैकल्पिक व्याख्याएँ सामने आईं और बहस का दायरा बढ़ा। हालांकि, इस विषय पर इतिहासकारों में एकमत नहीं है और विभिन्न लेखक अलग-अलग निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन-सा दावा अधिक लोकप्रिय है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उपलब्ध दस्तावेज किसी एक निष्कर्ष तक निर्णायक रूप से पहुँचाते हैं? अब तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और व्यापक रूप से स्वीकार किए गए ऐतिहासिक शोध के आधार पर इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है। यह स्थापित है कि भूमि का संबंध राजा जय सिंह से था, लेकिन यह प्रश्न कि उस स्थान पर पहले कौन-सी संरचना थी, आज भी विवाद और शोध का विषय बना हुआ है। इसी कारण अदालतों ने भी ऐसे मामलों में ठोस साक्ष्यों के महत्व पर बल दिया है। ताजमहल की बहस का पहला अध्याय किसी मंदिर या मकबरे से नहीं, बल्कि एक जमीन से शुरू होता है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि उस भूमि का संबंध राजा जय सिंह की संपत्ति से था। इसके आगे की कहानी वहाँ पहले क्या था, क्या बदला, क्या निर्मित हुआ यही वह हिस्सा है जहाँ दावे, दस्तावेज और व्याख्याएँ अलग-अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं।

कागजों का नागरिक

-कुमार कृष्णन

अपने ही देश के नागरिक को आखिर कितने दस्तावेज चाहिए? यह प्रश्न जितना सीधा दिखाई देता है, उसका उत्तर उतना ही उलझा हुआ है। यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतंत्र, नागरिकता और राज्य के चरित्र से जुड़ा हुआ सवाल है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली पहचान यह होनी चाहिए कि वह अपने नागरिक पर विश्वास करे। लेकिन जब नागरिक को हर कुछ वर्षों पर अपनी पहचान, अपना पता, अपना जन्म, अपनी जाति, अपनी आय, अपना निवास और कभी-कभी अपनी नागरिकता तक बार-बार प्रमाणित करनी पड़े, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर संदेह किस पर है—नागरिक पर या व्यवस्था की अपनी क्षमता पर? भारत में आज एक सामान्य नागरिक के पास दस्तावेजों की लंबी सूची है। जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खाते का केवाईसी, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, परिवार पहचान पत्र, स्वास्थ्य कार्ड, श्रमिक कार्ड, किसान पंजीकरण, पेंशन पहचान और न जाने कितने प्रमाणपत्र। इनमें से अधिकांश का उद्देश्य अलग-अलग बताया जाता है, किंतु नागरिक के अनुभव में ये सब अंततः उसी की पहचान को बार-बार सिद्ध करने की प्रक्रिया बन जाते हैं। विडंबना यह है कि एक सरकारी विभाग जिस दस्तावेज को अंतिम प्रमाण मानता है, दूसरा विभाग उसी पर भरोसा नहीं करता। कहीं आधार पर्याप्त नहीं होता तो कहीं मतदाता पहचान पत्र अमान्य हो जाता है। किसी योजना के लिए राशन कार्ड चाहिए, तो दूसरी के लिए निवास प्रमाणपत्र। तीसरी योजना में दोनों होने के बावजूद नया सत्यापन अनिवार्य हो जाता है। नागरिक के लिए यह केवल कागजों का बोझ नहीं, बल्कि समय, धन, श्रम और मानसिक थकान का भी बोझ है। सबसे अधिक कठिनाई उन लोगों के सामने आती है जो समाज के सबसे कमजोर तबकों से आते हैं। ग्रामीण भारत का गरीब, प्रवासी मजदूर, भूमिहीन किसान, बुजुर्ग, दिव्यांग, आदिवासी और बेघर व्यक्ति अक्सर उन्हीं दस्तावेजों के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित हो जाता है जिनके निर्माण की प्रक्रिया तक उसकी पहुँच सहज नहीं होती। जिन लोगों को राज्य की सबसे अधिक आवश्यकता है, वही लोग कागजी औपचारिकताओं के सबसे बड़े शिकार बन जाते हैं। डिजिटल भारत का सपना निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है। तकनीक प्रशासन को सरल, पारदर्शी और तेज बना सकती है।

भारत-यूके CETA से व्यापारिक संभावनाओं को मिलेगा नया बल

मुंबई (उत्तरशक्ति)। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा के अनुसार, भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) भारत की मुक्त व्यापार समझौता यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो एक व्यापक मुक्त व्यापार साझेदारी के माध्यम से दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक साथ लाता है। इस समझौते के तहत, ब्रिटेन को होने वाले भारत के 99% निर्यात को शुल्क-मुक्त (ड्यूटी-फ्री) पहुंच मिलेगी, जबकि भारत ने भी अपनी 89.5% टैरिफ लाइनों को ब्रिटेन के लिए खोल दिया है। श्री मिंडा ने रेखांकित किया कि इस समझौते से भारत के कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और रसायन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है। इसी तरह, ब्रिटेन को भी ऑटोमोटिव, पेय पदार्थ एवं स्पिरिट्स, लाइफ साइंसेज और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बड़ा फायदा होने वाला है।

उन्होंने आगे कहा कि यह शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच दोनों देशों की पूरकताओं का लाभ उठाकर, व्यापार की मात्रा बढ़ाकर, निवेश को बढ़ावा देकर और व्यापक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करके व्यापारिक संभावनाओं को नया बल देगी। यह ऐतिहासिक समझौता चार साल की निरंतर वार्ताओं का परिणाम है। श्री मिंडा ने CETA के जल्द से जल्द कार्यान्वयन की उम्मीद जताते हुए कहा कि इसके लाभ जल्द ही धरातल पर दिखने लगेंगे। उनके अनुसार, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025-26 के लगभग 58 बिलियन अमेरिकी डॉलर से करीब दोगुना होकर 2030 तक लगभग 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने का अनुमान है, जो भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करेगा।

एचपीसीएल ने इंस्टामार्ट पर लॉन्च किया अपना नया कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर ब्रांड एचपी नव्या

मुंबई (उत्तरशक्ति)। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने आज अपने अगली पीढ़ी के कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर ब्रांड एचपी नव्या का शुभारंभ किया। यह लॉन्च नवाचार और ग्राहकों की सुविधा के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। ग्राहकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए एचपीसीएल ने भारत के अग्रणी विवक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट के साथ साझेदारी की है, जिससे ग्राहक अब इंस्टामार्ट के माध्यम से आसानी से एचपी नव्या सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे। ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जहां तेज, सुविधाजनक और डिजिटल सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है, एचपीसीएल एलपीजी को पहले से अधिक सुलभ बनाने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर रहा है। इंस्टामार्ट के साथ यह साझेदारी ग्राहकों को घर बैठे एचपी नव्या सिलेंडर ऑर्डर करने और डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेगी। इस अवसर पर एचपीसीएल के निदेशक (मार्केटिंग) अमित गर्ग ने कहा ग्राहकों की आवश्यकताएं लगातार बदल रही हैं और एचपीसीएल उनकी जरूरतों के अनुरूप नवोन्मेषी समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सुरक्षा, भरोसे और विश्वसनीयता के साथ, जिनके लिए एचपी गैस जानी जाती है, 'नया भारत' के लिए एलपीजी को और अधिक सुलभ एवं सुविधाजनक बना रहे हैं। 'एचपी नव्या' हमारे नए कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर ब्रांड के रूप में हमारे उस संकल्प को दर्शाता है, जिसके तहत हम ऐसे ऊर्जा समाधान प्रदान कर रहे हैं जो लोगों के दैनिक जीवन को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाते हैं।

शक्ति पंप्स की सेल्सफोर्स के साथ पार्टनरशिप, एआई के जरिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव को मिलेगी रफ्तार

मुंबई। भारत की प्रमुख सोलर पंप निर्माता कंपनी और देश के रिन्यूएबल एनर्जी व कृषि बदलाव में अहम भूमिका निभाने वाली शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड ने आज दुनिया के नंबर 1 एजेंटिक एआई सीआरएम, सेल्सफोर्स के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है इस पार्टनरशिप के जरिए कंपनी अपनी एआई बेस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी को और तेज करेगी। इससे शक्ति पंप्स एक स्मार्ट और डेटा आधारित एंटरप्राइज बनाएगी, जो किसानों के साथ बेहतर जुड़ाव, बिजनेस की तेजी और कंपनी की अगली ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। यह पार्टनरशिप शक्ति पंप्स के उस विजन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसके तहत कंपनी एक प्रमुख सोलर पंप निर्माता से आगे बढ़कर एक व्यापक एग्री-टेक पार्टनर बनना चाहती है। एजेंटफोर्स सेल्स, एजेंटफोर्स सर्विस, एजेंटफोर्स मार्केटिंग, कंज्यूमर गुड्स क्लाउड, फील्ड सर्विस के लिए सेल्सफोर्स, टैब्लो नेक्स्ट, एजेंटफोर्स वाइब्स, और एजुकेशन के लिए एजेंटफोर्स की मदद से कंपनी अपने ग्राहकों, डीलर्स और फील्ड ऑपरेशंस को एक ही एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म पर लाएगी। इससे पूरे डीलर नेटवर्क पर रियल टाइम विजिबिलिटी मिलेगी, इंस्टॉलेशन और आफ्टर सेल्स सर्विस अधिक आसान और व्यवस्थित होगी, किसानों तक उनकी जरूरत के अनुसार पर्सनलाइज्ड तरीके से पहुंच बनाई जा सकेगी और टीमों को तेज, बेहतर और सही फैसले लेने के लिए डेटा आधारित इनसाइट्स मिलेंगे। शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश पाटीदार ने कहा, हम भारत के किसानों के लिए एक व्यापक एग्री-टेक पार्टनर बनने के अपने विजन पर लगातार काम कर रहे हैं। इस सफर में टेक्नोलॉजी और एआई हमारी ऑपरेशंस को बड़े स्तर पर बढ़ाने, डीलर्स के साथ मजबूत जुड़ाव बनाने और पूरे इकोसिस्टम में लगातार बेहतर वैल्यू देने में अहम भूमिका निभाएंगे।

सूर्या रोशनी ने आधुनिक घरों के लिए नए पंखे, वॉटर हीटर और किचन उपकरण पेश किए

मुंबई/पटना। सूर्या रोशनी लिमिटेड, लाइटिंग, वायर एवं केबल, पंखे, घरेलू उपकरण, पीवीसी पाइप, वॉटर पंप, वॉटर टैंक और स्टील पाइप्स के क्षेत्र में देश के सबसे भरोसेमंद नामों में से एक, ने अपने नए प्रीमियम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स उत्पादों की श्रृंखला लॉन्च करने की घोषणा की है। यह लॉन्च कंपनी की नवाचार, गुणवत्ता, सुरक्षा और बेहतर उपभोक्ता अनुभव देने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। नए प्रोडक्ट रेंज का लॉन्च कोलकाता में आयोजित एक चैनल पार्टनर मीट के दौरान किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल के साथ-साथ बिहार, झारखंड और ओडिशा के चैनल पार्टनर्स ने भी हिस्सा लिया। इस नई पेशकश में प्रीमियम डिजाइनर बीएलडीसी पंखे शामिल हैं, जिनमें स्लीक एयर डेको और स्मार्ट प्लस के साथ-साथ ज्वेल प्रो और रॉयल जैसे डेकोरेटिव पंखे शामिल हैं।

महाराष्ट्र का 'स्किल फर्स्ट' पैटर्न प्रशिक्षण, औद्योगिक साझेदारी और वैश्विक अवसरों का समन्वय

मुंबई (उत्तरशक्ति)। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग की ओर से आज एल्फिन्स्टन टेक्निकल हाईस्कूल, फोर्ट स्थित सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य में कौशल विकास को और अधिक सशक्त बनाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण उपक्रमों का शुभारंभ किया गया।

विश्व बैंक के सहयोग से दक्ष परियोजना के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पहल का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। प्रथम चरण में 240 प्रशिक्षकों को आधुनिक तकनीकों पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, CNC मशीनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्लंबर, सर्वेयर, वेल्डर तथा एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फिटर सहित विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा लार्सन एंड टुब्रो जैसी उद्योग संस्थाओं ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग के लिए पहल की है। इन समझौतों के माध्यम से भाषा प्रशिक्षण, प्रस्थान-पूर्व प्रशिक्षण, दस्तावेजों की पूर्ति, नियोक्ताओं के साथ समन्वय, डिजिटल ट्रैकिंग तथा प्लेसमेंट के बाद सहायता जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे विद्यार्थियों को देश एवं विदेश में रोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु आवश्यक सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध होगी। आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले की पृष्ठभूमि में आवश्यक कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सह्याद्री रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, नाशिक को 4,000 अभ्यर्थियों के पूर्व कौशल ज्ञान प्रमाणीकरण तथा 300 अभ्यर्थियों के लिए अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण संचालित करने हेतु आशय पत्र प्रदान किया गया। इस पहल से हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, ऑटोमोबाइल, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर WorldSkills Shanghai 2026 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित महाराष्ट्र के पाँच राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने घोषणा की कि यदि ये प्रतिभागी WorldSkills Shanghai 2026 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं तो उन्हें 5 लाख रुपये, रजत पदक विजेता को 3 लाख रुपये तथा कांस्य पदक विजेता को 2 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंबई-1 के Internet of Things (IoT) पाठ्यक्रम के 11 प्रशिक्षणार्थियों, जिन्हें प्रशिक्षण के दौरान ही रोजगार प्राप्त हुआ, का भी सम्मान किया गया। ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा ज्योतिबा फुले कौशल प्रशिक्षण केंद्र योजना के अंतर्गत दो प्रशिक्षण संस्थाओं को आशय पत्र (छड्क) प्रदान किए गए। साथ ही उरफ पहल के अंतर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को इंडोर जिम, खेल सामग्री तथा वाटर कूलर उपलब्ध कराने के लिए स्नेहधारा चैरिटी काउंसिल का विशेष सम्मान किया गया। इस अवसर पर मार्गदर्शन करते हुए मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालय स्तर से ही कौशल शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। भविष्य में कौशल का महत्व और अधिक बढ़ने वाला है। इसलिए, राज्य के कोने-कोने में रहने वाले प्रत्येक युवक-युवती, विशेष रूप से आदिवासी एवं दुर्गम क्षेत्रों के युवाओं तक आधुनिक कौशल प्रशिक्षण पहुँचाना समय की आवश्यकता है।

नौकरी के फर्जीवाड़े से बढ़ी चिंता, भारत के आधे नौकरी तलाशने वाले असली और नकली रिक्रूटर में फर्क नहीं कर पा रहे

मुंबई। इनडीड के 1,161 भारतीय कर्मचारियों पर किए गए एक सर्वे से पता चला है कि नौकरी के नाम पर बढ़ रही ठगी की वजह से लोगों का भरोसा कम हो रहा है। अब लोग नौकरी के ऑफर पर जल्दी भरोसा नहीं करते, जिससे कई बार अच्छी और असली नौकरियां भी उनके हाथ से निकल जाती हैं। भारत में नौकरी के नाम पर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। इससे लोगों का नौकरी की भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा कम हो रहा है। इनडीड की नई रिपोर्ट के अनुसार, 93% लोगों ने कभी न कभी फर्जी या शक वाली नौकरी के ऑफर देखे हैं। वहीं, 51% लोगों का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आता कि नौकरी देने वाला असली है या ठग। जैसे-जैसे नौकरी से जुड़े ठगी के मामले बढ़ रहे हैं और ठग नए-नए तरीके अपना रहे हैं, वैसे-वैसे नौकरी तलाशने वाले लोग अधिक सतर्क हो गए हैं। अब कई लोग तभी किसी भर्तीकर्ता यानी रिक्रूटर से बात करते हैं या नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, जब उन्हें उस अवसर के सही और भरोसेमंद होने का यकीन हो। इससे असली कंपनियों के लिए भी सही उम्मीदवारों तक पहुंचना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है।

इनडीड के टैलेंट स्ट्रैटेजी एडवाइजर रोहन सिल्वेस्टर ने कहा, आजकल नौकरी की भर्ती का काम तेजी से ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। नौकरी तलाशने वाले लोग यह जानना चाहते हैं कि जिस नौकरी के लिए वे आवेदन कर रहे हैं, वह सच में सही है या नहीं। वहीं कंपनियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनके नाम पर कोई ठगी करता है, तो इससे उनकी छवि खराब हो सकती है।

डॉ. बत्रा'ज ने पेश किया हेयरजेन, 50 बिलियन एक्सोसोम्स द्वारा संचालित भारत का पहला उन्नत हेयर रीग्रोथ उपचार

मुंबई (उत्तरशक्ति)। रिजनरेटिव मेडिसिन में एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए, डॉ. बत्रा'ज हेल्थकेयर ने आज हेयरजेन के लॉन्च की घोषणा की। यह 50 बिलियन एक्सोसोम्स द्वारा संचालित भारत का पहला उन्नत हेयर रीग्रोथ उपचार है, जो बालों को वापस पाने के लिए गैर-सर्जिकल समाधान चाहने वाले रोगियों के लिए दुनिया की सबसे आशाजनक रिजनरेटिव तकनीकों में से एक को लेकर आया है। बालों का झड़ना अब केवल कॉस्मेटिक चिंता का विषय नहीं रह गया है। यह पूरे भारत में सभी आयु वर्ग के 15 करोड़ लोगों के लिए भावनात्मक और आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाला मुद्दा बन चुका है। हेयरजेन को उन सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए बनाया गया है जो बाल झड़ने की किसी भी समस्या से परेशान हैं, चाहे वह आनुवंशिक गंजापन हो, डिलीवरी के बाद बालों का झड़ना हो, मेनोपॉज के बाद बालों का पतला होना हो, मानसिक तनाव के कारण बाल गिरना हो या फिर शुरूआत में ही बाल हल्के होना हो। यह सीधे स्कैल्प पर असरदार सिग्नल भेजकर सोई हुई जड़ों को फिर से जगाता है, सिर की त्वचा को तंदुरुस्त बनाता है और शरीर में प्राकृतिक रूप से बाल उगाने की प्रक्रिया को तेज करता है। इससे समय के साथ बाल पहले से ज्यादा घने, मजबूत और चमकदार दिखने लगते हैं।

इस लॉन्च के बारे में बात करते हुए, डॉ. बत्रा'ज हेल्थकेयर के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, तथा ट्राइकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय अध्यक्ष, डॉ. अक्षय बत्रा ने कहा, हेयर रिस्टोरेशन एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश कर रहा है। आज के उपभोक्ता ऐसे समाधान चाहते हैं जो विज्ञान पर आधारित हों, जिनमें कोई चीर फाड़ न हो और जो शरीर की अपनी रिजनरेटिव प्रणाली के साथ मिलकर काम करके प्राकृतिक रूप से बाल उगा सकें। एक्सोसोम थेरेपी रिजनरेटिव मेडिसिन में सबसे रोमांचक प्रगतियों में से एक है, क्योंकि यह शक्तिशाली जैविक संकेत भेजती है जो सोई हुई बालों की जड़ों को जगाने और बालों के प्राकृतिक विकास में मदद करती है।

रईस हाई स्कूल में मशहूर शायर अजीज नबील का किया गया भव्य स्वागत, विद्यार्थियों से किया संवाद

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर, साहित्यकार एवं चिंतक अजीज नबील ने सद्भावना भेंट के तहत भिवंडी स्थित रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का दौरा किया। संस्थान पहुंचने पर वाईसीएमओयू स्टडी सेंटर के समन्वयक अब्दुल अजीज अंसारी ने उन्हें स्कूल मैगजीन, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक, विद्यार्थी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अजीज नबील ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से आत्मीय संवाद करते हुए संस्थान की शैक्षणिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सराहना की तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज विद्यार्थियों के सर्वांगीण शैक्षणिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। यही कारण है कि यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर संस्थान के साथ-साथ भिवंडी का नाम भी गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संस्थान भविष्य में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, श्रेष्ठ संस्कार और उत्कृष्ट शैक्षणिक परंपराओं को इसी समर्पण के साथ आगे बढ़ाता रहेगा। समारोह के अंत में अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया।

सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, घायल कबड्डी खिलाड़ी को दी 5 लाख की आर्थिक सहायता

पीड़ित को मिलने पहुंचे महेश गायकवाड़

कल्याण (उत्तरशक्ति)। इंसानियत सबसे बड़ी ताकत होती है, इसका एक बार फिर परिचय कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने अपनी संवेदनशील पहल से दिया है। गंभीर चोट के कारण उपचार के लिए आर्थिक संकट से जूझ रहे जिला स्तरीय उत्कृष्ट कबड्डी खिलाड़ी सुमित सालुंखे को उन्होंने 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की। ऐसी जानकारी महेश गायकवाड़ ने दिया है,

इस सहायता से न केवल सुमित सालुंखे के इलाज को बड़ा सहारा मिला है, बल्कि उनके जीवन में नई उम्मीद भी जगी है। कठिन समय में आगे बढ़कर मदद करने की सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे की संवेदनशीलता, मानवीय दृष्टिकोण और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की व्यापक सराहना हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉ. श्रीकांत शिंदे हमेशा जरूरतमंदों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी यह पहल एक बार फिर साबित करती है कि जनप्रतिनिधि का दायित्व केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं होता, बल्कि संकट में लोगों का साथ देना भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सुमित सालुंखे और उनके परिवार ने इस महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग के लिए सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मदद से उनके उपचार की राह आसान हुई है और उन्हें भविष्य के लिए नई उम्मीद मिली है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक की दिशा में पालघर की बड़ी पहल

57 सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का NQAS प्रमाणन अभियान तेज, 8 को मिला राष्ट्रीय प्रमाणन

पालघर(उत्तरशक्ति)। पालघर जिला प्रशासन व जिला स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक अभियान को तेज कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ, मरीज-केंद्रित और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। जिले में कुल 57 सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को ठदअर प्रमाणन के लिए चयनित किया गया है। इनमें से 39 संस्थानों ने राज्य स्तरीय वैलिडेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जबकि 8 स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्रीय ठदअर प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। वहीं 20 अन्य संस्थान विभिन्न चरणों में प्रमाणन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। जिला प्रशासन ने जुलाई 2026 तक 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अगस्त 2026 तक 28 आयुष्मान आरोग्य मंदिर-उपकेंद्र (अअट-रउ) को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन दिलाने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 126 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को रिक्त उपकेंद्रों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। साथ ही जिले को 5 प्रशिक्षित ठदअर मूल्यांकनकर्ताओं (2 राष्ट्रीय और 3 राज्य स्तरीय) का सहयोग मिल रहा है, जो स्वास्थ्य संस्थानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। प्रमाणन प्रक्रिया में भी तेजी आई है। अब तक 28 स्वास्थ्य संस्थानों ने सक्षम पोर्टल पर आवेदन किया है, जबकि जुलाई 2026 में 8 संस्थानों के मूल्यांकन का कार्यक्रम तय हो चुका है। इसके अलावा 6 संस्थानों को फायर एनओसी प्राप्त हो चुकी है, जबकि शेष संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा करने की प्रक्रिया जारी है। जिला प्रशासन के अनुसार जव्हार, तलासरी व दहानू तहसीलों में प्रमाणन कार्य संतोषजनक गति से चल रहा है, जबकि पालघर, वसई, वाडा और विशेष रूप से मोखाडा में प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेष तकनीकी सहायता और नियमित समीक्षा की जा रही है। हालांकि अभियान के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। इनमें स्वास्थ्य संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं की कमी, प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं की सीमित उपलब्धता, लंबित फायर एनओसी, एम्बुलेंस और चालकों की उपलब्धता, अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता तथा NQAS अंतर-पूर्ति (Gap Funding) के लिए समर्पित निधि का अभाव प्रमुख हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती में तेजी, मूल्यांकनकर्ताओं की संख्या बढ़ाना, फायर एनओसी समय पर प्राप्त करना, सक्षम पोर्टल पर लंबित आवेदन शीघ्र पूर्ण करना, जरूरत वाले क्षेत्रों में विशेष समीक्षा बैठकें आयोजित करना तथा आपातकालीन रेफरल सेवाओं को मजबूत किया जायेगा। जिलाधिकारी डॉ. इंदू रानी जाखड़ ने विश्वास जताया कि स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों के संयुक्त प्रयासों से पालघर जिला निर्धारित समय में ठदअर प्रमाणन का लक्ष्य हासिल करेगा तथा जिले के नागरिकों को और अधिक गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।

एमईटी पीजीडीएम को एआईयू से एमबीए के समकक्ष मान्यता मिली

मुंबई। मुंबई का एमईटी इंस्टीट्यूट ऑफ पीजीडीएम हमेशा से अपनी इंडस्ट्री-ओरिएंटेड पढ़ाई, दोहरी विशेषज्ञता और नए जमाने के आधुनिक विषयों के लिए जाना जाता रहा है। यहां छात्रों को मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, बिजनेस एनालिटिक्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और स्टार्टअप्स व न्यू एंटरप्राइज मैनेजमेंट जैसे नए विषय पढ़ने को मिलते हैं। अब इस साख में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) ने संस्थान के इस दो साल के फुल-टाइम पीजीडीएम प्रोग्राम को आधिकारिक तौर पर एमबीए के समकक्ष मान्यता दे दी है। इस फैसले के बाद, अब यहां से पास होने वाले छात्रों को भी वही शैक्षणिक दर्जा और वैल्यू मिलेगी, जो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से एमबीए डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को मिलती है। व्यावहारिक रूप से देखें तो, यह मान्यता एमईटी के छात्रों के लिए कई नए रास्ते खोलती है। अब वे भारत और विदेशों में डॉक्टरल प्रोग्राम करने के लिए पूरी तरह योग्य माने जाएंगे। इसके साथ ही, वे सरकारी संगठनों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और नियामक संस्थाओं में नौकरियों के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। जहां भी एमबीए या उसके समकक्ष डिग्री मांगी जाएगी, वहां एमईटी के छात्र बराबरी से योग्य माने जाएंगे। यह बदलाव मैनेजमेंट शिक्षा की बदलती तस्वीर को दिखाता है। आज के समय में ऑटोनॉमस पीजीडीएम संस्थान लगातार ऐसी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं जो सीधे तौर पर उद्योगों की जरूरतों को पूरा करे। वहीं दूसरी तरफ, छात्र भी ऐसी योग्यता चाहते हैं जो व्यावहारिक रूप से काम आए और आगे की पढ़ाई के रास्ते भी खोले। एआईयू की यह समकक्षता इस अंतर को दूर करने का काम करती है। यह योग्य पीजीडीएम प्रोग्राम्स को विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली एमबीए डिग्री के समान शैक्षणिक दर्जा देती है मौजूदा छात्रों और पूर्व छात्रों दोनों के लिए ही, यह मान्यता उस असमंजस को पूरी तरह खत्म कर देती है जो उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पीजीडीएम की स्वीकार्यता को लेकर लंबे समय से बना हुआ था। इसके साथ ही, यह उन छात्रों के लिए विदेश जाने के रास्ते भी आसान बनाती है जो आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे देशों का रुख करना चाहते हैं। विदेशी विश्वविद्यालय अक्सर एडमिशन देते समय डिग्रियों की शैक्षणिक समकक्षता की जांच करते हैं, और अब एमईटी के छात्रों को वहां भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस मान्यता पर टिप्पणी करते हुए एमईटी के ट्रस्टी पंकज भुजबळ ने कहा इआज के छात्र उम्मीद करते हैं कि उनकी मैनेजमेंट की पढ़ाई उन्हें हर करियर के लिए तैयार करे-चाहे वह कॉर्पोरेट लीडरशिप हो, उद्यमिता हो, रिसर्च हो, पब्लिक पॉलिसी हो या फिर आगे की उच्च शिक्षा। एआईयू की यह समकक्षता यह पक्का करती है कि हमारे छात्रों के पास ऐसी शैक्षणिक मान्यता हो जिससे वे बिना किसी रुकावट के अपने सपनों को पूरा कर सकें। अलग-अलग उद्योगों में फैले हमारे मजबूत एलुमनाई नेटवर्क के साथ मिलकर, यह मान्यता हमारे पीजीडीएम की अहमियत को और बढ़ाती है।

नीम करौली बाबा

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालयः
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाप हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामी: शरद फागुराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुद्रित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पुणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाप हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

शटर में उतर रहे करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, दो मासूमों के सिर से उठा पिता का साया

खेतासराय,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। बुधवार की सुबह थाना क्षेत्र के तारगहना गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया घर के मुख्य शटर में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से 41 वर्षीय युवक की मौत हो गई घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया जबकि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार तारगहना गांव निवासी अच्छेलाल बिंद के 41 वर्षीय पुत्र शिवपूजन बिंद अपने परिवार के साथ रात में छत पर सोए हुए थे भोर में तेज हवा और बारिश शुरू होने पर परिवार के लोग सामान समेटने के लिए नीचे आने लगे इसी दौरान शिवपूजन घर के मुख्य शटर को खोलने पहुंचे परिजनो ने बताया कि शटर के पास से गुजर रही बिजली की केबल कहीं से क्षतिग्रस्त थी, जिससे शटर में करंट प्रवाहित हो गया था। जैसे ही शिवपूजन ने शटर को हाथ लगाया, उन्हें जोरदार करंट का झटका लगा।

झटके से वह पास में रखे तख्त पर गिर पड़े और सिर में गंभीर चोट लगने के बाद अचेत हो गए। परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल, जौनपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। शिवपूजन पिकअप चालक थे और उसी की कमाई से पूरे परिवार का भरण-पोषण होता था। उनके निधन से पत्नी चन्देरखा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा शिवपूजन अपने पीछे दो मासूम बच्चों पुत्र शिवांश और पुत्री आंषि को छोड़ गए पिता की असमय मौत से दोनों बच्चों के सिर से साया उठ गया घटना के बादपरिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है।

स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन, मेडिकल कॉलेज व निजी अस्पतालों की अव्यवस्थाओं पर उठाई आवाज

सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड में लंबी प्रतीक्षा, चिकित्सकों की कमी व अवैध अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की मांग

सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। जनपद सोनभद्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर काशी क्षेत्र मीडिया प्रभारी विपिन तिवारी ने उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल तथा निजी अस्पतालों में व्याप्त गंभीर अव्यवस्थाओं पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आम जनता को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि सोनभद्र मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल में मरीजों को आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। चिकित्सकों और संसाधनों की कमी के कारण मरीजों को उपचार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। वहीं सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सहित अन्य महत्वपूर्ण जांचों के लिए लंबी-लंबी तिथियां मिलने से गंभीर मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे दूर-दराज के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

ज्ञापन में जिले में बिना मानकों के संचालित हो रहे निजी अस्पतालों एवं अवैध क्लीनिकों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। आरोप लगाया गया कि कई निजी चिकित्सा संस्थान स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा और जीवन दोनों खतरे में पड़ रहे हैं। ऐसे अस्पतालों एवं क्लीनिकों की व्यापक जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।

काशी क्षेत्र मीडिया प्रभारी विपिन तिवारी ने कहा कि सोनभद्र एक आदिवासी एवं पिछड़ा जनपद है, जहां बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल में आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने, जांच सुविधाओं को सुचारु एवं समयबद्ध बनाने तथा अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और क्लीनिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

ज्ञापन के माध्यम से यह भी अपेक्षा जताई गई कि जनहित से जुड़े इन गंभीर मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्री शीघ्र संज्ञान लेकर प्रभावी कदम उठाएंगे, ताकि जिले के लाखों नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें तथा स्वास्थ्य व्यवस्था में जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो।

केराकत में धार्मिक स्थल की जमीन को लेकर विवाद गहराया, पैमाइश में 904 वर्गफुट भूमि पर कब्जे का दावा

प्रियेश गुप्ता रुद्रा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत तहसील क्षेत्र के थानागद्दी गांव में धार्मिक स्थल की भूमि को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मंदिर की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मजार और कथित मस्जिद का निर्माण किया गया है। इस संबंध में प्रशासन को दिए गए ज्ञापन के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश की।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, थानागद्दी बाजार से मजार की ओर जाने वाली पतली गली सहित बड़ी मजार का आधे से अधिक हिस्सा तथा छोटी मजार पूरी तरह मंदिर की भूमि पर निर्मित है। उनका दावा है कि मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर उसे मजार के रूप में विकसित किया गया।

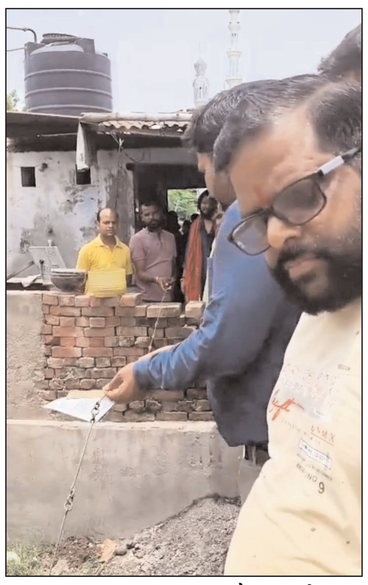

बताया जा रहा है कि लेखपाल की टीम द्वारा की गई पैमाइश में कथित रूप से लगभग 904 वर्गफुट भूमि मंदिर की बताई गई, जिस पर कब्जा होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, इस मामले में राजस्व विभाग या जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। साथ ही दूसरे पक्ष का भी पक्ष सामने नहीं आया है।

प्रशासन का कहना है कि पैमाइश की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले को देखते हुए क्षेत्र में स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है।

वहीं यह समाचार शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों और उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। वास्तविक स्थिति एवं अंतिम निष्कर्ष प्रशासनिक जांच और सक्षम अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा।

जौनपुर महिला से मारपीट का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत क्षेत्र में महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। केराकत कोतवाली पुलिस ने सोहनी गांव निवासी परशुराम यादव को उसके घर से गिरफ्तार किया। वायरल वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ केराकत थाने में बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए अभियुक्त का चालान कर न्यायालय भेज दिया। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है, वहीं पुलिस का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

एचपीसीएल का मनाया गया स्थापना दिवस

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 52वें स्थापना दिवस के मौके पर विमल गैस सर्विस, सुक्खीपुर जौनपुर द्वारा बुधवार को अपने शोरूम परिसर में ग्राहकों को पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्राहकों को पौधों का वितरण किया गया साथ ही परिसर में पौधरोपण भी किया गया, साथ ही सुरक्षा नियमों की उन्हें जानकारी भी दी गई। यह कार्यक्रम विमल गैस सर्विस के प्रोप्राइटर रतन सोनकर के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस मौके पर अमित श्रीवास्तव, लालजी सोनकर, अभिषेक गुप्ता, फारिस खान, पतिराम यादव, प्रदीप मौर्या, दिलीप जायसवाल, अरविन्द कश्यप आदि लोग मौजूद रहे।

पूर्व विधायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा भवन लखनऊ का भ्रमण

केराकत, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत विधानसभा के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी जौनपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश चौधरी ने करवाया अपने कार्यकताओं को विधानसभा का भ्रमण दिनांक 13 जुलाई दिन सोमवार को विधानसभा क्षेत्र केराकत के करीब ढाई सौ से अधिक वर्तमान मंडल के पदाधिकारी पूर्व मंडल के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकताओं को पूर्व विधायक दिनेश चौधरी ने बड़े ही भाव के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र केराकत के सम्मानित कार्यकताओं को विधानसभा भवन का भ्रमण करवाया।

विधान भवन के अंदर सदन वाले हाल में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव के हाथों से सम्मानित कार्यकताओं को पूर्व विधायक दिनेश चौधरी ने अंग वस्त्र दिलवा करके उनका सम्मान करवाया उनके हौसलों को बढ़ाया। क्षेत्र में पूर्व विधायक के इस पहल की बहुत चर्चा है। कार्यकर्ता कह रहे हैं इतिहास में ऐसा कोई कार्य किसी

जनप्रतिनिधि ने आज तक नहीं किया। पूर्व विधायक के इस सराहनीय पहल की कार्यकर्ता एवं जनता जनार्दन में बहुत चर्चा है। पूर्व विधायक ने कहा कि अभी यह पहले टोली में लेकर के विधानसभा भ्रमण करवाने आया हूं। अभी दूसरी टोली में बचे हुए कार्यकताओं को भी विधानसभा का भ्रमण करवाऊंगां। पूर्व विधायक ने कहा कि कार्यकताओं का सम्मान ही मेरा सम्मान है। मेरे लिए बूथ पर लड़ाई लड़ने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता मेरे लिए सम्माननीय हैंआदरणीय हैं। मैं इन लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए सदैव अपने आप को समर्पित करके रखता हूं।

पूर्व विधायक ने जो कार्य कर दिया वह कार्य आज तक पूर्वांचल के किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया है ऐसा भी लोगों में चर्चा है।

चुम्मी कांडः वायरल वीडियो के बाद प्राइमरी स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका निलंबित, जांच शुरू

कन्नौज (उत्तरशक्ति)। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक

शिक्षक और शिक्षिका का कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने दोनों को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि वीडियो कई माह पुराना है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लिया।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता मानते हुए दोनों शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं।

शिक्षा विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और मामले की गहन जांच जारी है।

इस घटना के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और विद्यालयों में अनुशासन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

धमार्पुर में ब्लॉक स्तरीय स्कूल चलो अभियान रैली एवं गोष्ठी का आयोजन, मुख्य अतिथि रहे बीएसए समीर

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। विकास खंड धमार्पुर में स्कूल चलो अभियान (द्वितीय चरण) के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय रैली एवं गोष्ठी का आयोजन किया

गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर रहे। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी धमार्पुर, शिक्षक-शिक्षिकाएं, शिक्षामित्र, अनुदेशक, अभिभावक तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं पुष्पगुच्छ भेंट के साथ हुआ। अपने संबोधन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर ने कहा कि ₹कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।₹ उन्होंने शिक्षकों से घर-घर संपर्क कर विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराने का आह्वान किया।

इसके बाद निकाली गई जागरूकता रैली ने क्षेत्रवासियों को शिक्षा के महत्व, नियमित विद्यालय उपस्थिति तथा परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध निःशुल्क सुविधाओं के प्रति जागरूक किया। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को विद्यालय की मुख्यधारा से जोड़ते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

7 अगस्त को निकलेगी बोल बम कांवड़ यात्रा की भव्य शोभायात्रा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। बोल बम कांवड़िया संघ, जौनपुर द्वारा आगामी 7 अगस्त 2026 (शुक्रवार) को बाबा बैद्यनाथ धाम जलाभिषेक के लिए विशाल कांवड़ यात्रा एवं भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इस संबंध में संघ के महासचिव विमल सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र देकर आवश्यक प्रशासनिक सहयोग, सुरक्षा व्यवस्था और सुचारु यातायात की मांग की है।

पत्र के अनुसार, शोभायात्रा सुबह 8 बजे हनुमान घाट, चौरा माता मंदिर (गोमती तट) से घोड़े, भगवान शिव की आकर्षक झांकियों, भजन-कीर्तन और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ प्रारंभ होगी। यात्रा सद्भावना पुल, ओलंदगंज, कजगांव पड़ाव, शाही पुल, चहारसू चौराहा, कोतवाली चौराहा, सब्जी मंडी और सुतहट्टी बाजार होते हुए भंडारी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वहां से श्रद्धालु

प्रशासन से सुरक्षा व यातायात व्यवस्था की मांग

फरक्का एक्सप्रेस द्वारा सुल्तानगंज रवाना होंगे और गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए पदयात्रा करेंगे।

संघ ने बताया कि मार्ग खराब होने तथा बिजली के खंभों और तारों की समस्या के कारण इस वर्ष शोभायात्रा का रूट परिवर्तित किया गया है। साथ ही प्रशासन से अंडरग्राउंड बिजली बॉक्स को सुरक्षित ढंकने, बिजली के तार ऊंचे कराने, पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती तथा कार्यक्रम के दौरान सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

बोलबंग कांवड़िया संघ के अनुसार, हर वर्ष की तरह इस बार भी विभिन्न मोहल्लों से शिवभक्त झांकियों और भजन मंडलियों के साथ यात्रा में शामिल होंगे तथा मार्ग में अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं श्रद्धालुओं के स्वागत और जलपान की व्यवस्था करेंगी।

सोनम वांगचुक के अनशन की उपेक्षा लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीतः पवन कुमार सिंह एडवोकेट

सुशील कुमार तिवारी

सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। पूर्वांचल राज्य जनमोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव पवन कुमार सिंह एडवोकेट ने नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण एवं जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर लंबे समय से अनशन पर बैठे समाजसेवी सोनम वांगचुक की लगातार हो रही उपेक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण एवं अहिंसक आंदोलन जनता की आवाज होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इतने दिनों से अनशन पर बैठा है और अब तक सरकार अथवा प्रमुख जनप्रतिनिधियों द्वारा उनसे संवाद स्थापित करने का गंभीर प्रयास नहीं किया गया है, तो यह लोकतांत्रिक संवेदनशीलता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। आगे पवन कुमार सिंह एडवोकेट ने कहा कि किसी भी जनआंदोलन का समाधान संवाद और सकारात्मक पहल से ही संभव है। सरकार एवं सभी जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सोनम वांगचुक से वार्ता करें, उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करें तथा लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए शीघ्र समाधान की दिशा में सार्थक कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, पर्यावरण एवं देश के भविष्य से जुड़े विषय केवल किसी एक व्यक्ति के नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के सरोकार हैं। ऐसे मुद्दों पर संवेदनशीलता, संवाद और सकारात्मक निर्णय समय की आवश्यकता है।

प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनता इण्टरमीडिएट कालेज बीरभानपुर के प्रांगण में 2025-26 के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के मेधावी छात्र-छात्राओं को विद्यालय की प्रबन्धक उर्मिला सिंह एवं प्रधानाचार्य आनन्द प्रकाश सिंह ने गोल्ड मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात छात्रों को मिष्ठान वितरण करके सम्मानित किया। जैसे ही छात्र पुरस्कार प्राप्त किये, प्रफुल्लित एवं अपने को गौरवान्वित महसूस करते हुये उछलने–कूदने लगे। सभी शिक्षकों ने उज्जवल भविष्य का कामना किया। साथ ही आगे और अच्छा परिश्रम करने का मार्ग से अवगत कराया। छात्रों में अति उत्साह देखा गया जहां बच्चों ने विद्यालय के प्रति आभार ज्ञापित किया। अन्त में जितेन्द्र सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। छात्र-छात्राओं ने स्व. समरजीत सिंह की प्रतिमा के समक्ष पूरे स्टाफ के साथ पुष्पांजलि अर्पित किया। साथ ही उन्हें याद करते हुये उनके सपनों को साकार करने का संकल्प किया।

16 माह से जाम नाली बनी मुसीबत

घरों में भर रहा गंदा पानी, मानीकलां के लोगों में आक्रोश

डॉ.इम्तियाज अहमद

मानीकलां, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। विकास खंड सोंधी शाहगंज क्षेत्र के कस्बा मानीकलां में कम्पोजिट विद्यालय के निकट स्थित मस्जिद जन्नतुल फिरदौस के पश्चिमी हिस्से की नाली पिछले करीब 16 माह से जाम पड़ी है। नाली की नियमित सफाई नहीं होने से घरों का गंदा पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिससे जलभराव और गंदगी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी ने रोस्टर के अनुसार सफाई कराए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक मौके पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

नाली जाम होने से गंदा पानी गलियों और घरों के आसपास जमा हो रहा है। इससे दुर्गंध फैल रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बरसात के मौसम में हालात और भी बदतर हो गए हैं, जिससे लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

एक ओर जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत गांवों और कस्बों में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दे रहे हैं, वहीं मानीकलां में लंबे समय से जाम नाली प्रशासनिक दावों की पोल खोलती नजर आ रही है।

स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से तत्काल नाली की सफाई कराकर जल निकासी व्यवस्था बहाल करने तथा लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

समस्या उठाने वालों में फिरोज अहमद, अल्ताफ अहमद, मोहम्मद अरशद, नदीम अनवर, मौलाना नसीम, हकीमुद्दीन, हाफिज तबरेज, मोहम्मद फैज, रेहान अहमद, रियाजुद्दीन, शकील अहमद, इश्तियाक अहमद, शाहनवाज अहमद, रियाज अहमद, निजामुद्दीन, मो. सालिम खान और मोहम्मद हैदर सहित अनेक स्थानीय नागरिक शामिल हैं।

रेणुकूट में 500 पौधों का रोपण, 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान को मिला जनसमर्थन

रेणुकूट,सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 'वृक्षारोपण महायज्ञ' अभियान के अंतर्गत 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल को आगे बढ़ाते हुए रेणुकूट स्थित आश्रम पार्क के समीप नोखई पम्पहाउस के नजदीक व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन हिण्डाल्को पर्यावरण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी), सोनभद्र के क्षेत्रीय अधिकारी के निर्देशानुसार किया गया।

इस अवसर पर प्रातः 11 बजे लगभग 500 पौधों का सफलतापूर्वक रोपण किया गया। कार्यक्रम में उद्यान (हॉर्टिकल्चर) टीम के समन्वय से विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए, जिससे क्षेत्र की हरित आच्छादन को बढ़ावा मिल सके।

वृक्षारोपण अभियान में गार्डेन विभाग की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। सभी ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया।

इस मौके पर उपस्थित पर्यावरण विभाग के प्रमुख श्री सत्यजीत आचार्या ने कहा कि ‟एक पेड़ माँ के नाम‟ अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक है, जो प्रकृति और मातृत्व दोनों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। उन्होंने बताया कि इस तरह के प्रयास न केवल पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में सहायक हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यक्रम का सफल संचालन पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री अनिल सिंह द्वारा किया गया। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया, जिसमें सभी को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर विवेक मिश्रा, अलोक उपाध्याय, अम्बरीष सिंह, प्रभात द्विवेदी, महेन्द्र तिवारी, कुमुद यादव, हरिओम केसरी, ज्ञाना दास एवं गार्डेन तथा पर्यावरण विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

नगरसेवक आमिर नसीम खान का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया गया

मुंबई, 13 जुलाई 2026। वॉर्ड क्रमांक 162 के नगरसेवक आमिर नसीम खान का जन्मदिन उनके जरीमरी स्थित जनसंपर्क कार्यालय में सादगी एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाजसेवक सुखविंदर सिंह (लाला भाई), सुखबीर सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिकों एवं समर्थकों ने शॉल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर आमिर नसीम खान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं जनसेवा के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं। जन्मदिन समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों का आमिर नसीम खान ने आत्मीय स्वागत किया और अल्पाहार की व्यवस्था के साथ सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में शुभचिंतकों ने भाग लेकर उन्हें शुभकामनाएं दीं।

शहरी शिविरों से आयुर्वेद से हुए 315 नागरिक लाभान्वित

उदयपुरवाटी । राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहर के नागरिकों एवं ग्रामीणों को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत एवं शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन 12 जून से 15 जुलाई तक हुआ।आयोजित सेवा शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा आम लोगों की समस्याओं का यथासंभव मौके पर समाधान किया गया। नगरपालिका द्वारा चलाए गए शहरी सेवा शिवरों में आयुर्वेद विभाग की सेवाएं भी रही। ब्लॉक आयुर्वेद नोडल अधिकारी डॉ राजेंद्र कुमावत ने बताया कि 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित हुए शिविरों में अब तक 315 नागरिक आयुर्वेद चिकित्सा से लाभान्वित हुए हैं। बुधवार को हुए शिविर मे ब्लॉक आयुष चिकित्सालय के डॉ.वीरेंद्र कुमार सैनी व पूजा शर्मा नर्स ने ड्यूटी दी तथा आज 21 जनों को जीवनशैली जन्य परामर्श व 13 को उपलब्ध औषध देकर उपचार किया।

एड. अवनीश तीर्थ राज सिंह का जन्मदिन मनाया गया

मुंबई। लन्दन पैलेस साधना इंडस्ट्रियल इस्टेट, दूसरा माला, जोगेश्वरी वेस्ट में उत्तर भारतीय समाज के सामाजिक जनसेवकों, सभी पार्टियों के नेता, विशिष्ट सम्मानित लोग उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। इसी कड़ी में डॉ सचिन सिंह,युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष, अड़ शरीफ खान, मनोज सिंह,डॉ आर एम पाल तथा मुलुंड के प्रतिष्ठित लोगों ने उपस्थित दर्ज कराते हुए जन्मदिन की शुभकामनायें दी, जीवन में सफलता पाने का आशीर्वाद प्रदान किया।

वसई के लिए अलग पुलिस मुख्यालय की मांग पर डीजीपी सदानंद दाते से स्नेहा दुबे पंडित ने की मुलाकात

मुंबई। वसई की विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सदानंद दाते से शिष्टाचार (गुडविल) मुलाकात कर वसई-विरार क्षेत्र के लिए अलग पुलिस मुख्यालय स्थापित किए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। मुलाकात के दौरान विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने कहा कि वसई-विरार की तेजी से बढ़ती आबादी, लगातार हो रहे शहरीकरण तथा कानून-व्यवस्था से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए मीरा-भायंदर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत वसई डिवीजन के लिए अलग पुलिस मुख्यालय की स्थापना समय की आवश्यकता है।

उन्होंने बताया कि अलग पुलिस मुख्यालय बनने से नागरिकों को अधिक प्रभावी, त्वरित और सुलभ पुलिस सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने कहा कि वसई के नागरिकों की सुरक्षा, बेहतर पुलिस व्यवस्था और आधुनिक प्रशासनिक सुविधाओं के लिए उनका प्रयास लगातार जारी रहेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस महत्वपूर्ण मांग पर सकारात्मक पहल होने से क्षेत्र के लाखों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।

इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 में करिश्मा कपूर ने साझा किए 90 के दशक के 5 यादगार डांस किस्से

पटना। इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 में जज के रूप में करिश्मा कपूर ने 90 के दशक की अपनी फिल्मों और लोकप्रिय गीतों से जुड़े कई दिलचस्प अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि झांझरिया गाने के महिला संस्करण की शूटिंग के दौरान उन्हें 20 बार कॉस्ट्यूम बदलने पड़े थे।करिश्मा ने हसीना मान जाएगी के लोकप्रिय गीत मोबाइल नंबर क्या है की शूटिंग से जुड़ा किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी गोवा पर आधारित थी, लेकिन यह गीत मुंबई के मड आइलैंड में एक दिन में फिल्माया गया था। उन्होंने कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट के शुरूआती दिनों को याद करते हुए बताया कि सहायक कोरियोग्राफर के रूप में वह रिहर्सल के दौरान बेहद अनुशासित और मेहनती थीं। वहीं दिल तो पागल है को अपने करियर की सबसे लंबी रिहर्सल वाली फिल्म बताते हुए करिश्मा ने कहा कि इस फिल्म के लिए उन्होंने लंबे समय तक अभ्यास किया। करिश्मा कपूर ने कोरियोग्राफर चिन्नी प्रकाश और रेखा प्रकाश के साथ अपने शुरुआती अनुभव भी साझा किए और बताया कि उनके सख्त प्रशिक्षण ने उन्हें एक बेहतर कलाकार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 का प्रसारण हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर किया जाता है।

आबादी की जमीन विवाद में पुलिस कार्रवाई पर सवाल, डीएम से निष्पक्ष जांच की मांग

जौनपुर (उत्तरशक्ति) । सुजानगंज थाना क्षेत्र के नाहरमऊ टिकरा गांव निवासी किरन सिंह पत्नी मुन्ना सिंह ने जिलाधिकारी जौनपुर को प्रार्थना पत्र देकर पड़ोसियों और स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उनकी पुस्तैनी आबादी की जमीन पर जबरन कब्जा कर रास्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर पड़ोसी संजय सिंह व नीलम सिंह ने कथित रूप से पुलिस और लेखपाल की मिलीभगत से निर्माण कराने की कोशिश की। शिकायत के बावजूद 10 जुलाई 2026 की रात पुलिस बिना महिला पुलिसकर्मियों के उनके घर में घुस गई, अभद्र व्यवहार किया, सामान में तोड़फोड़ की और उन्हें तथा उनकी देवरानी को थाने ले जाकर कई घंटे बैठाए रखा। घर लौटने पर उन्होंने कथित रूप से देखा कि विवादित स्थान पर रास्ता खुलवा दिया गया था। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि 28 जून 2026 को भी उन्हें और उनकी देवरानी को थाना ले जाकर बाद में धारा 151 के तहत उपजिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इन घटनाओं से उनका परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है तथा जान-माल का खतरा बना हुआ है।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव जनसंवाद में बोले- काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं

प्रणित नरेंद्र तिवारी

इंदौर (उत्तरशक्ति)। इंदौर में बुधवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने विधानसभा-4 के वार्ड-क्र 72 स्थित रेवेन्यू नगर गार्डन में जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं सुनीं। रहवासियों ने गार्डनों के रखरखाव, स्ट्रीट लाइटों के नियमित मेंटेनेंस, ड्रेनेज लाइन की सफाई और कुछ गलियों में जलभराव की शिकायतें रखीं। इस पर महापौर ने नगर निगम अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, ताकि नागरिकों को बार-बार शिकायत दर्ज न करानी पड़े। उन्होंने अधिकारियों से रखरखाव व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। जनसंवाद के बाद महापौर सच्चिदानंद नगर योगशाला पहुंचे, जहां उन्होंने पौधारोपण किया और योग करने आए लोगों से क्षेत्र की सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम केवल दैनिक रखरखाव तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले 20 से 25 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर शहर का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जा रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि पेयजल और ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 25 वर्ष पुरानी पाइपलाइनें बदली गई हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को देखते हुए नर्मदा परियोजना के चौथे चरण पर काम आगे बढ़ाया गया है। शहर के विभिन्न हिस्सों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 मास्टर प्लान सड़कों का निर्माण तेजी से चल रहा है। कई सड़कें पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष परियोजनाओं पर काम जारी है। इनके पूरा होने से यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी ।

पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेने की अपीलविकसित किए जा रहे हैं। परियोजनाओं पर काम तेजी से जारी है। इनके पूरा होने से यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी। महापौर ने लोगों से पीएम सूर्य घर (सौर ऊर्जा) योजना का लाभ उठाने और अपने घरों पर सोलर पैनल लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे बिजली बिल में कमी आएगी और केंद्र सरकार की सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि इंदौर में अब तक 32 हजार से अधिक परिवार अपने घरों पर सोलर पैनल लगा चुके हैं। जनसंवाद के अंत में महापौर ने रेवेन्यू नगर स्थित गार्डन में खराब झूलों, चकरी और व्यायाम उपकरणों को हटाकर उनकी जगह नए झूले और आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे।

विंढमगंज वन क्षेत्र में बालू का अवैध खनन जारी

विंढमगंज, सोनभद्र (उत्तरशक्ति)। स्थानीय थाना एवं वन क्षेत्र के अंतर्गत कनहर,मलिया नदी में इन दिनों रात में अबैध खनन का खेल चल रहा है। जिनके कंधों पर अवैध धंधे रोकने की जिम्मेदारी है वह कथित हिस्सेदारी लेकर मौन हैं। सूत्रों की मानें तो खननकर्ता दिन भर बालू के ग्राहकों की तलाश में विंढमगंज क्षेत्र के झारखंड से सटे आसपास के गांवों में घूमते रहते हैं और ऑर्डर लेकर रात को तय रणनीति के तहत मौन स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र के नदियों से अवैध खनन का खेल शुरू हो जाता है। अर्धरात्रि के बाद से शुरू होकर खनन का खेल बेखौफ सुबह सात बजे तक चलता रहता है।

पर्यावरण प्रेमियों व बुद्धजीवी ग्रामीणों की मानें तो जहाँ पूरे प्रदेश में खनन बन्द कर दिया गया हैं लेकिन विंढमगंज क्षेत्र में अबैध खनन रुकने का नाम नही ले रहा हैं विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के मिलीभगत से मलिया नदी तथा कनहर नदी से प्रतिदिन दर्जनों ट्रैक्टर खनन में लिप्त बताए जा रहे हैं।कोरगी पतरिहा से होते हुए महुली पहुंच कर अपने गंतव्य को पहुँचते है।

ग्रामीणों की मानें तो जिम्मेदारों या अधिकारियों की आने की सूचना अवैध खननकर्ताओ तक पहले पहुँच जाती हैं।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस प्रजनन काल मे भी आस पास के नदियों में चल रहे अवैध खनन की गोपनीय जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाई की मांग की है । ताकि नदियों का अस्तित्व बचा रहे। इस सम्बंध में डीएफओ रेनुकूट से संपर्क करने की कोशिश किया गया लेकिन फोन नही लगने के कारण सम्पर्क नही हो सका।

कांग्रेस टढरउ की ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए मजबूती से खड़ी है, भूख हड़ताल का सातवां दिन

नवीमुंबई। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 'एक्शन मोड' में नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी पार्टी लीडरशिप सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आई है। पार्टी के कई कार्यकर्ता उइऊ बेलापुर में टढरउ ऑफिस के ठीक सामने बारी-बारी से भूख हड़ताल कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि टढरउ की परीक्षाएं ऑफलाइन हों, इस विरोध-प्रदर्शन की अगुवाई महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस नेता और नवी मुंबई यूनिट के प्रेसिडेंट रामचंद्र 'आबा' दलवी कर रहे हैं। टढरउ परीक्षाएं ऑनलाइन कराने के फैसले को लेकर छात्रों में काफी नाराजगी है। यह कदम इस फैसले का विरोध करने, परीक्षाएं ऑफलाइन कराने की मांग करने और छात्रों व उनकी जायज मांग के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल करने के मकसद से उठाया जा रहा है। नवी मुंबई में टढरउ के हेड ऑफिस के सामने, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के रोजगार और स्वरोजगार विभाग के चेयरमैन धनंजय शिंदे और नवी मुंबई ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामचंद्र दलवी की अगुवाई में क्रमिक भूख हड़ताल और धरना-प्रदर्शन शुरू किया गया है। भूख हड़ताल में भाग लेने वाले पदाधिकारियों में धनंजय शिंदे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस रोजगार और स्वरोजगार विभाग), रामचन्द्र दलवी (अध्यक्ष, नवी मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी), हारिस शेकासन, सुश्री जगताप, सुश्री साल्वे, सैय्यद नासिर हुसैन, सुरेंद्र प्रसाद, प्रदीपकुमार सकपाल, संतोष सुतार, तुकाराम कदम, साहेब एस. यादव, प्रतीक यादव और एडवोकेट बिलाल मुल्ला शामिल हैं।

मासूम बच्ची का अपहरण कर बेचने जा रहे पांच आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ। चौक थाना पुलिस ने 18 माह की बच्ची के अपहरण का 48 घंटे के भीतर पदार्फाश करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रभारी निरीक्षक नागेश उपाध्याय के अनुसार, आरोपित बच्ची को बेचने की फिराक में थे। गिरोह के दो अन्य सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। डीसीपी पश्चिमी जोन के निर्देशन में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर बुधवार सुबह गुलजार नगर क्षेत्र से पांचों आरोपितों को दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह बच्चों की खरीद-फरोख्त के उद्देश्य से मासूम बच्चों की तलाश करता था।

पुलिस के मुताबिक, 13 जुलाई की रात चौक क्षेत्र स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज के पास सो रहे दंपती के बीच से 18 माह की बच्ची का अपहरण किया गया था। आरोपित बच्ची को बाइक से गुलजार नगर ले गए और उसकी फोटो व वीडियो गिरोह के सरगना को भेजी। बच्ची उम्र में अपेक्षाकृत बड़ी होने के कारण पसंद नहीं आई, जिसके बाद उसे मछली मंडी के पास बने पुल पर छोड़ दिया गया और आरोपी दूसरे बच्चे की तलाश में निकल पड़े।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान ऋषभ कश्यप, रोहित पासी उर्फ जादू, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद इरशाद शाह और श्याम जी यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से अपहृत बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही चार मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अधिकारी वरिष्ठ उपनिरीक्षक अखिलेश मिश्र ने बताया कि गिरोह के सरगना शेर सिंह और सहयोगी महेश फरार हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। आरोपितों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है।

पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के प्रयासों से दूध व्यापारियों को राहत

मुंबई/वसई। उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के प्रयासों से वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्र के मांडवी में स्थित विवान मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से जुड़े दूध व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (टढउइ) की कार्रवाई के बाद बंद की गई बिजली आपूर्ति को फिर से शुरू किए जाने से सैकड़ों दूध व्यापारियों का कारोबार फिर से पटरी पर आ गया है।

बिजली आपूर्ति बंद होने से पैदा हुई गंभीर समस्या को लेकर गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष सिद्धेश ज्योति रामदास कदम से मुलाकात कर तुरंत समाधान निकालने की मांग की। इस प्रतिनिधिमंडल में शिवसेना उत्तर भारतीय आघाडी के जिलाध्यक्ष शिवदयाल मिश्रा के साथ-साथ दूध व्यापारियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बैठक के दौरान व्यापारियों ने बताया कि बिजली आपूर्ति बंद होने

MPCB अध्यक्ष कदम के हस्तक्षेप के बाद बिजली आपूर्ति फिर शुरू

के कारण दूध और दुग्ध उत्पादों का उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया था। इससे सैकड़ों व्यापारियों और उन पर निर्भर परिवारों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ा था। इससे पहले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के ठाणे क्षेत्रीय कार्यालय ने पर्यावरणीय नियमों के कथित गंभीर उल्लंघन के कारण मांडवी स्थित विवान मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स (सर्वे क्रमांक 76, गांव मांडवी, ता. वसई, जि. पालघर) के खिलाफ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33-अ और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-अ के तहत संबंधित विभागों को बिजली और पानी की आपूर्ति तुरंत बंद करने के आदेश दिए थे। इसके अनुसार बिजली वितरण विभाग ने बिजली कनेक्शन काट दिया था। इस मौके पर गोपाल शेट्टी ने कहा कि पर्यावरणीय नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई का खामियाजा बेकसूर दूध व्यापारियों को नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के संबंधित निर्देशों का हवाला देते हुए सुझाव दिया कि बकाया बिजली बिल या अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर बिजली आपूर्ति शुरू की जाए और उद्योग को जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाए। गोपाल शेट्टी के अनुरोध के बाद टढउइ अध्यक्ष सिद्धेश ज्योति रामदास कदम ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।इसके बाद बिजली आपूर्ति फिर से शुरू कर दी गई। इससे प्रभावित दूध व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है और उनका कारोबार फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गया है। दूध व्यापारियों ने गोपाल शेट्टी और टढउइ अध्यक्ष सिद्धेश ज्योति रामदास कदम का आभार जताते हुए कहा कि उनके त्वरित और संवेदनशील हस्तक्षेप से सैकड़ों परिवारों की आजीविका बच गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी जनहित के मुद्दों पर जनप्रतिनिधि और प्रशासन इसी तरह संवेदनशील भूमिका निभाएं।

जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट, कई घायल; पीड़ित ने पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार

जितेन्द्र कन्नौजिया

केराकत, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। थाना क्षेत्र के उदयचंदपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर मंगलवार सुबह दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

पीड़िता गायत्री देवी पत्नी झगड़ू ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि दिनेश, रमेश, भोला, चंदन, रतन, प्रिया समेत अन्य लोग एकजुट होकर उनकी जमीन पर निर्माण कार्य कराने पहुंचे थे। विरोध करने पर विपक्षियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।

आरोप है कि मारपीट के दौरान पीड़िता के पुत्र इंदल पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे उसकी गर्दन में गंभीर चोट आई। वहीं पीड़िता के साथ भी डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। घटना में परिवार के अन्य सदस्यों के घायल होने की भी जानकारी दी गई है।

पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्षियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की।

वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

17 जुलाई की जनरल बॉडी बैठक में बाढ़ की स्थिति पर होगी चर्चा , मनोज पाटिल, मेयर अजीव पाटिल ने विपक्ष के नेता की मांग को दी मंजूरी

विरार। वसई-विरार शहर में 4 से 8 जुलाई के बीच हुई भारी बारिश और बाढ़ की गंभीर स्थिति पर अब वसई-विरार महानगरपालिका की जनरल बॉडी बैठक में विस्तृत चर्चा होगी। विपक्ष के नेता मनोज पाटिल द्वारा की गई मांग को स्वीकार करते हुए मेयर अजीव पाटिल ने 17 जुलाई 2026 को होने वाली मासिक जनरल मीटिंग में इस महत्वपूर्ण विषय को चर्चा के लिए शामिल करने की मंजूरी दे दी है।

मनोज पाटिल ने महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1949 का हवाला देते हुए विशेष बैठक बुलाने की मांग की थी। उनका कहना था कि हालिया बाढ़ से शहर के कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ और भविष्य में

ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस एवं समयबद्ध योजना आवश्यक है। दरअसल, महानगरपालिका की मासिक बैठक 8 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन भारी बारिश और बाढ़ के कारण उसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह बैठक 17 जुलाई 2026, शुक्रवार, दोपहर 3:00 बजे महानगरपालिका सभागृह में आयोजित होगी।

बैठक में विपक्ष के नेता ने प्रशासन से वर्ष 2018 से शहर की भौगोलिक संरचना के अध्ययन के आधार पर ठएएफक्र और क्क्ळ द्वारा तैयार तकनीकी रिपोर्ट पर अब तक की गई कार्रवाई, उस पर हुए खर्च, नालों की सफाई, आपदा प्रबंधन व्यवस्था तथा भविष्य की समयबद्ध कार्ययोजना का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखने की मांग की है। इसके अलावा बैठक में कुल 12 अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा और मंजूरी दी जाएगी। इनमें पुरानी पेंशन योजना लागू करने तथा पूर्व ग्राम पंचायत कर्मचारियों को लाभ देने, दो सहायक आयुक्तों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रस्ताव, महानगरपालिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नए सेवा ढांचे को मंजूरी, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता, 13वीं राष्ट्रीय मेयर मैराथन 2026 के आयोजन के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, ट्री अथॉरिटी विभाग के लिए आधुनिक हाइड्रोलिक सीढ़ियां एवं वाहन खरीदने तथा नायगांव-बापने रोड पर बॉक्स कल्वर्ट निर्माण से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

विपक्ष के नेता मनोज पाटिल ने उम्मीद जताई है कि सदन में होने वाली विस्तृत चर्चा से बाढ़ नियंत्रण, जलनिकासी व्यवस्था और नागरिकों को स्थायी राहत देने के लिए प्रभावी निर्णय लिए जाएंगे।

रुद्राक्ष में जुटेंगे चार राज्यों के 500 ग्राम प्रधान, पंचायतों के सशक्तीकरण पर होगा मंथन

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद में 16 जुलाई 2026 को वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले पंच सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधान एक मंच पर जुटेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने के साथ ही VB-GRAM G Act, 2025 के प्रावधानों एवं उद्देश्यों के प्रति जनप्रतिनिधियों की समझ को और मजबूत करना है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान तथा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश से 350, बिहार से 75, झारखंड से 50 और उत्तराखंड से 25 ग्राम प्रधान भाग लेंगे। कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों की संस्थागत तैयारियों को सुदृढ़ करने, विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से सहभागी एवं साक्ष्य-आधारित विकास को बढ़ावा देने, पंचायत स्तर पर विभिन्न योजनाओं के बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा जमीनी स्तर पर प्रभावी सुशासन को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सम्मेलन के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों को नई व्यवस्थाओं और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।

श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन

वृंदावन। पूज्या श्री जीता पंडित जी के मुखारविंद से श्रीधाम वृंदावन स्थित महर्षि आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य एवं दिव्य आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ चल रहा है। कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होकर शाम को आरती के साथ सम्पन्न होती है। कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। इस अवसर पर जनपद जौनपुर के सिकरारा स्थित मुकुंदीपुर निवासी कथा सहयोगी यजमान दिवाकर मिश्र सपरिवार कथा में सहभागिता कर रहे है।

न्यूजीलैंड की ऊन महंगी, भारतीय कालीन उद्योग ने मांगा समाधान

वाराणसी। भारत के हस्तनिर्मित कालीन उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल मानी जाने वाली न्यूजीलैंड की प्रीमियम ऊन की लगातार बढ़ती कीमत और सीमित उपलब्धता अब निर्यातकों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इस गंभीर मुद्दे को भारत टेक्स-2026 के दूसरे दिन आयोजित भारत-न्यूजीलैंड उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) ने स्पष्ट किया कि यदि गुणवत्तापूर्ण न्यूजीलैंड ऊन की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हुई तो भारतीय कालीन उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है। 14 से 17 जुलाई तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स-2026 के दौरान हुई इस बैठक में दोनों देशों के व्यापारिक सहयोग को नई ऊंचाई देने और वस्त्र एवं ऊन क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में न्यूजीलैंड प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के ग्रामीण समुदाय एवं कृषि राज्यमंत्री मार्क पैटरसन ने किया। भारतीय पक्ष की ओर से कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष कैप्टन मुकेश गोम्बर ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके साथ परिषद के उपाध्यक्ष असलम महबूब, कार्यवाहक कार्यकारी निदेशक डॉ. स्मिता नागरकोटी तथा प्रमुख निर्यातक जफर इकबाल अंसारी (ईस्टर्न मिल्स) और कैप्टन विजेंद्र जगलान (हेरिटेज ओवरसीज) मौजूद रहे।

बैठक के दौरान सीईपीसी ने कहा कि न्यूजीलैंड की ऊन की कीमतों में लगातार वृद्धि से भारतीय कालीन निर्माताओं की उत्पादन लागत तेजी से बढ़ी है। इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय कालीनों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर पड़ रहा है। परिषद ने यह भी बताया कि केवल कीमत ही नहीं, बल्कि ऊन की सीमित उपलब्धता भी निर्यातकों के लिए गंभीर संकट बनती जा रही है। इससे उत्पादन प्रभावित होने के साथ विदेशी खरीदारों की समयबद्ध मांग पूरी करना भी कठिन हो रहा है।

सीईपीसी ने जोर देकर कहा कि यदि प्रीमियम गुणवत्ता वाली न्यूजीलैंड ऊन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तो भारतीय निर्माता अधिक मूल्य वाले उत्कृष्ट कालीन तैयार कर सकेंगे। इससे उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ेगी, निर्यात में वृद्धि होगी और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। बैठक में दोनों देशों ने मौजूदा व्यापारिक व्यवस्था का अधिक प्रभावी उपयोग करने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने तथा वस्त्र और ऊन क्षेत्र में नए सहयोगी अवसर तलाशने पर भी विस्तार से चर्चा की। सीईपीसी के अध्यक्ष कैप्टन मुकेश गोम्बर ने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक संबंधों में अपार संभावनाएं हैं। यदि कच्चे माल की कीमतों और गुणवत्तापूर्ण ऊन की नियमित आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया जाता है तो भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि परिषद भविष्य में भी न्यूजीलैंड के साथ निकट सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। परिषद के उपाध्यक्ष असलम महबूब ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बदलती परिस्थितियों के बीच विदेशी साझेदारों के साथ लगातार संवाद बेहद आवश्यक है। न्यूजीलैंड की ऊन अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण भारतीय हस्तनिर्मित कालीन उद्योग की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसकी बेहतर उपलब्धता से मूल्य संवर्धित उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजार में नए अवसर प्राप्त होंगे।

प्रमुख निर्यातक जफर इकबाल अंसारी ने कहा कि ऊन की बढ़ती कीमतों से अधिक चिंता उसकी उपलब्धता को लेकर है। निर्यात बाजार की मांग पूरी करने और उत्पादन की निरंतरता बनाए रखने के लिए गुणवत्तापूर्ण ऊन की नियमित आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है। बैठक का समापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच वस्त्र एवं कालीन क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने तथा दोनों देशों के बीच निरंतर संवाद जारी रखने की साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ। सीईपीसी ने दोहराया कि वह अंतरराष्ट्रीय सहयोग, व्यापार संवर्धन और वैश्विक भागीदारी के माध्यम से भारत के हस्तनिर्मित कालीन उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेगा।

हरहुआ रिंग रोड पर देर रात मिला मूक-बधिर बालक, पुलिस ने चौकी लाकर कराई देखभाल

वाराणसी(उत्तरशक्ति) जनपद के हरहुआ में मंगलवार की मध्य रात्रि हरहुआ रिंग रोड चौराहे पर गश्त और क्षेत्र चेकिंग के दौरान हरहुआ चौकी प्रभारी विवेकानंद त्रिवेदी को एक मूक-बधिर बालक अकेला घूमता हुआ मिला। देर रात बालक के सड़क पर भटकने को देखते हुए पुलिस ने उसे सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया। चौकी प्रभारी विवेकानंद त्रिवेदी अपने हमराहियों के साथ बालक को हरहुआ पुलिस चौकी लेकर पहुंचे, जहां उसे चाय-नाश्ता कराया गया और उसकी देखभाल की गई। इसके बाद पुलिस ने इशारों और अन्य माध्यमों से बालक का नाम, पता और परिजनों की जानकारी लेने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसके मूक-बधिर होने के कारण कोई जानकारी नहीं मिल सकी। फिलहाल पुलिस बालक की पहचान कराने और उसके परिजनों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। यदि किसी व्यक्ति को इस बालक के संबंध में कोई जानकारी हो तो वह हरहुआ पुलिस चौकी या बड़ागांव थाना से संपर्क कर सकता है, ताकि उसे सकुशल उसके परिवार तक पहुंचाया जा सके।

Sotefin Bharat Limited का IPO 16 जुलाई को खुलेगा

मुंबई। रोबोटिक और ऑटोमेटेड पार्किंग सॉल्यूशन देने वाली कंपनी Sotefin Bharat Limited अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) गुरुवार, 16 जुलाई, 2026 को खोलने जा रही है। इसका मकसद 89.76 करोड़ (अपर प्राइस बैंड पर) जुटाना है और शेयरों को इरए रटए प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया जाएगा। इश्यू का साइज 10 फेस वैल्यू वाले 48,00,000 इक्विटी शेयर तक है और प्राइस बैंड 178-187 प्रति शेयर है।

IPO से मिलने वाली नेट रकम का इस्तेमाल कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरतों को पूरा करने, प्रस्तावित नए ऑफिस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरतों को पूरा करने, कंपनी की वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए किया जाएगा। एंकर बिडिंग बुधवार, 15 जुलाई, 2026 को होगी। इश्यू गुरुवार, 16 जुलाई, 2026 को खुलेगा और सोमवार, 20 जुलाई, 2026 को बंद होगा।

इस इश्यू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर Choice CÔpitÔl Advisors PrivÔte Limited है और रजिस्ट्रार BigshÔre Services PrivÔte Limited है। सोतेफिन भारत लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, अरूप चौधरी ने कहा, शुरूआत से ही सोतेफिन भारत ने इंजीनियरिंग की बेहतरीन क्षमता और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के दम पर नए और ऑटोमेटेड पार्किंग सॉल्यूशन देने पर लगातार ध्यान दिया है। हमारा आने वाला IPO हमारी ग्रोथ की यात्रा में एक अहम पड़ाव है, जिससे हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ा सकेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना सकेंगे और काम करने की अपनी क्षमता को और मजबूत कर सकेंगे।

चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, रतराज टिबरेवाल ने कहा, इंजीनियरिंग इनोवेशन और ऑटोमेटेड पार्किंग सॉल्यूशन पर सोतेफिन भारत के फोकस ने इसे एक खास और बढ़ते हुए मार्केट में बड़ा बिजनेस बनाने में मदद की है। हमें यकीन है कि यह IPO कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, काम करने की क्षमता को मजबूत करने और पूरे भारत में स्मार्ट पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देगा।

CBSE का बड़ा फैसला: 10वीं का पास सर्टिफिकेट पाने के लिए तीसरी भाषा का इंटरनल असेसमेंट पास करना होगा

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। नई दिल्ली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए तीसरी भाषा (R3) को लेकर बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड के 10 जुलाई को जारी सर्कुलर के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2027-28 से कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्रों के लिए तीसरी भाषा का स्कूल-आधारित इंटरनल असेसमेंट पास करना अनिवार्य होगा। नए नियम के तहत यदि कोई छात्र तीसरी भाषा के इंटरनल असेसमेंट में सफल नहीं होता है, तो उसे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन (कक्षा 10) का पास सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, तीसरी भाषा की अलग से बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसका मूल्यांकन संबंधित विद्यालय द्वारा आंतरिक स्तर पर किया जाएगा। उइए ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2027-28 में कक्षा 10 में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर लागू होगी। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे तीसरी भाषा के आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करें, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

मानसून में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर एमबीवीवी पुलिस की विशेष पहल

पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक के मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समन्वय बैठक, दुर्घटना रोकथाम और ट्रैफिक सुचारु रखने पर हुआ मंथन

मीरा भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा रोड मानसून के दौरान यातायात बाधित होने की समस्याओं और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से मीरा-भाईंदर, वसई-विरार (एमबीवीवी) पुलिस आयुक्तालय में बुधवार को एक विशेष समन्वय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक के मार्गदर्शन में पुलिस आयुक्त कार्यालय के संवाद हॉल में संपन्न हुई। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), मीरा-भाईंदर महानगरपालिका तथा वसई-विरार महानगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर मानसून के समय यातायात को सुचारु बनाए रखने, जलभराव एवं अन्य बाधाओं का समयबद्ध निवारण करने तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी उपायों को लागू करने पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय शिंदे ने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि बारिश के दौरान नागरिकों को यातायात संबंधी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

कोनगांव में सांसद सुरेश म्हात्रे ने प्रशासन की मदद से जेसीबी से खुलवाया ग्रामीणों का बंद रास्ता

भिवंडी। कोनगांव स्थित गुरुचरण भूमि पर कथित अतिक्रमण कर नागरिकों के पारंपरिक आवागमन मार्ग को बंद किए जाने के मामले में भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेश म्हात्रे (बाल्या मामा) बुधवार को स्वयं मौके पर पहुंचे। प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से बंद रास्ता खुलवाया और लगाए गए टीन शेड (पत्रे) हटाए गए। बताया गया कि मेगास सिटी परियोजना से जुड़े बिल्डर मयूर सूचक पर गुरुचरण भूमि पर अतिक्रमण कर ग्रामीणों का वर्षों पुराना रास्ता बंद करने का आरोप है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना था कि क्षेत्र के तालाब और कुएं से आदिवासी महिलाओं एवं अन्य ग्रामीणों को पानी भरने से भी रोका जा रहा था। शिकायत मिलने पर सांसद सुरेश म्हात्रे ने तहसीलदार और गट विकास अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद तहसीलदार अभिजीत खोले के नेतृत्व में प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से रास्ते पर किए गए कथित अतिक्रमण को हटाकर मार्ग आम नागरिकों के लिए खोल दिया। इस दौरान तहसीलदार अभिजीत खोले, गट विकास अधिकारी सुधाकर खामकर, कोनगांव पुलिस थाने के अधिकारी, ग्राम पंचायत की सरपंच रेखा पाटिल, पूर्व सरपंच डॉ. रुपाली अमोल कराले सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, महिलाएं और आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित रहे। सांसद सुरेश म्हात्रे ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर जनता का रास्ता बंद करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में दोबारा रास्ता बंद करने का प्रयास किया गया तो अतिक्रमण के साथ-साथ अवैध निर्माण के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नवनिर्मित मकानों से विद्युत वायर चोरी करने वाले अभ्यस्त 03 शातिर चोर गिरफ्तार

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद में पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी के पर्यवेक्षण में, सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर व प्रभारी निरीक्षक चितईपुर के कुशल नेतृत्व में थाना चितईपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-174/2026 एवं मु०अ०सं०-175/2026 में निमार्णाधीन मकानों से विद्युत वायरिंग के तार चोरी होने की घटनाओं के अनावरण हेतु पुलिस टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर पतारसी-सुरागरसी कर रही थी। दिनांक 15.07.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की घटना में शामिल तीन व्यक्ति चोरी किए गए विद्युत वायर को बेचने के उद्देश्य से हाई ड्रिल के बगल स्थित खाली मैदान में स्कूटी के साथ मौजूद हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना चितईपुर पुलिस एवं क्राइम टीम ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

साइन यूनिसेक्स सैलोन एंड स्पा सेंटर में मसाज की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, मालकिन गिरफ्तार

मीरा भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा रोड महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय की महिला अत्याचार प्रतिबंधक, विशेष बालक संरक्षण एवं देखभाल कक्ष की टीम ने काशीगांव पुलिस थाना क्षेत्र में संचालित साइन यूनिसेक्स सैलोन एंड स्पा सेंटर पर छापेमारी कर मसाज की आड़ में चल रहे कथित देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर की मालकिन को गिरफ्तार किया गया तथा एक पीड़ित युवती को रेस्क्यू कर सुरक्षित संरक्षण में भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मीरा रोड पूर्व स्थित हाटकेश क्षेत्र के जीसीसी क्लब के पास, लोधा कासा परिसर की दुकान नंबर-10 में स्थित साइन यूनिसेक्स सैलोन एंड स्पा सेंटर में मसाज के नाम पर अनैतिक देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर महिला अत्याचार प्रतिबंधक, विशेष बालक संरक्षण एवं देखभाल कक्ष की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शीतल मुंढे के नेतृत्व में टीम ने बोगस ग्राहक और पंच की सहायता से छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर की मालकिन को गिरफ्तार कर लिया तथा एक पीड़ित युवती को रेस्क्यू किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्पा सेंटर की मालकिन ग्राहकों को मीरा-भाईंदर और वसई-विरार क्षेत्र के विभिन्न लॉजिंग एवं बोर्डिंग में भी युवतियां उपलब्ध कराती थी। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस कथित सेक्स रैकेट में उसके अन्य सहयोगी कौन हैं तथा अब तक कितनी युवतियों को मसाज के नाम पर देह व्यापार में धकेला गया है। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 143 तथा अनैतिक देह व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम (पीटा एक्ट) की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है। वहीं, रेस्क्यू की गई पीड़िता को महिला सुधारगृह भेजने की विधिक प्रक्रिया जारी है। यह कार्रवाई एमबीवीवी पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच के डीसीपी संदीप डोईफोडे तथा एसीपी बांगर के निर्देशन में की गई। अभियान में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शीतल मुंढे, एएसआई राजाराम आसवाले, एचसी किशोर पाटील, चेतन राजपूत, महिला पुलिस एचसी निशिगंधा मांजरेकर, शीतल जाधव, पीसी ललित पाटील तथा क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एमईटी पीजीडीएम को एआईयू से एमबीए के समकक्ष मान्यता मिली

मुंबई। मुंबई का एमईटी इंस्टिट्यूट ऑफ पीजीडीएम हमेशा से अपनी इंडस्ट्री-ओरिएंटेड पढ़ाई, दोहरी विशेषज्ञता और नए जमाने के आधुनिक विषयों के लिए जाना जाता रहा है। यहां छात्रों को मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, बिजनेस एनालिटिक्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और स्टार्टअप्स व न्यू एंटरप्राइज मैनेजमेंट जैसे नए विषय पढ़ने को मिलते हैं। अब इस साख में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है: एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) ने संस्थान के इस दो साल के फुल-टाइम पीजीडीएम प्रोग्राम को आधिकारिक तौर पर एमबीए के समकक्ष मान्यता दे दी है। इस फैसले के बाद, अब यहां से पास होने वाले छात्रों को भी वही शैक्षणिक दर्जा और वैल्यू मिलेगी, जो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से एमबीए डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को मिलती है। व्यावहारिक रूप से देखें तो, यह मान्यता एमईटी के छात्रों के लिए कई नए रास्ते खोलती है। अब वे भारत और विदेशों में डॉक्टरल प्रोग्राम करने के लिए पूरी तरह योग्य माने जाएंगे। इसके साथ ही, वे सरकारी संगठनों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और नियामक संस्थाओं में नौकरियों के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। जहां भी एमबीए या उसके समकक्ष डिग्री मांगी जाएगी, वहां एमईटी के छात्र बराबरी से योग्य माने जाएंगे। यह बदलाव मैनेजमेंट शिक्षा की बदलती तस्वीर को दिखाता है। आज के समय में ऑटोनॉमस पीजीडीएम संस्थान लगातार ऐसी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं जो सीधे तौर पर उद्योगों की जरूरतों को पूरा करे।

ज़िया एंटरप्राइजेज में ग्रीनलैम शॉपी का शुभारंभ

पालोजोरी। ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज ने झारखंड के पालोजोरी स्थित ज़िया एंटरप्राइजेज में नए ग्रीनलैम शॉपी का शुभारंभ किया। यह शोरूम जियाउल हक के प्रतिष्ठान, मंदिर चौक, सारठ रोड, पालोजोरी, देवघर 814146, झारखंड में स्थित है। यहां ग्रीनलैम के प्रीमियम लैमिनेट कलेक्शन प्रदर्शित किए गए हैं, जिससे ग्राहकों, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनरों और ठेकेदारों को एक ही स्थान पर विभिन्न सजावटी सरफेस सॉल्यूशंस उपलब्ध होंगे। ग्रीनलैम शॉपी का उद्घाटन ज़िया एंटरप्राइजेज के मालिक अजरूअल हक ने ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज के कंट्री हेड (ग्रीनलैम लैमिनेट एंड एलाइड) अनुज संगल तथा कंपनी की टीम की उपस्थिति में किया।

देवघर में पहले ग्रीनलैम शॉपी का शुभारंभ, झारखंड में रिटेल नेटवर्क हुआ मजबूत

देवघर। ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज ने झारखंड के देवघर स्थित रुद्रा प्लाईवुड में अपने पहले ग्रीनलैम शॉपी का शुभारंभ किया। पालिका बाजार चौक, असम एक्सप्रेस रोड, देवघर झा 814112 स्थित इस 500 वर्ग फुट के शोरूम में 100 वर्ग फुट का विशेष ग्रीनलैम डिस्प्ले एरिया बनाया गया है। यहां ग्रीनलैम 1.00 मिमी कलेक्शन, ग्रीनटच 0.80 मिमी कलेक्शन और लेक्सस 1.50 मिमी कलेक्शन प्रदर्शित किए गए हैं, जिससे घर के मालिकों, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनरों, ठेकेदारों और ट्रेड पार्टनर्स को डेकोरेटिव सरफेस सॉल्यूशंस की व्यापक रेंज उपलब्ध होगी। ग्रीनलैम शॉपी का उद्घाटन रुद्रा प्लाईवुड के प्रोपराइटर श्रीकांत केशरी ने किया। इस अवसर पर ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज के कंट्री हेड (ग्रीनलैम लैमिनेट एंड एलाइड) अनुज संगल तथा कंपनी की टीम मौजूद रही। लॉन्च कार्यक्रम में क्षेत्र के लगभग 30 ठेकेदारों और प्रमुख ट्रेड पार्टनर्स ने भाग लिया।

सांसद श्रीकांत शिंदे से नवजात शिशुओं की बेहतर इलाज की मांग

मुंबई। अंधेरी पूर्व मरोल के वार्ड क्रमांक 86 के युवा नगरसेवक रितेश कमलेश राय ने नवजात शिशुओं के अंधेरी में बेहतर इलाज की मांग को लेकर सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे को पत्र सौपा गया है। अपने पत्र के माध्यम से राय ने मांग की है कि अंधेरी स्थित कूपर हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर में नवजात शिशुओं के लिए ठक्ऊव अर्थात जिसमें बच्चों को सुरक्षित रखा जाता है कि संख्या तुरंत बढ़ाना चाहिए। जो आवश्यकता के अनुसार दोनों हॉस्पिटल में बहुत ही कम है। रितेश राय ने शिंदे से कहा है कि ढ्ढउव की संख्या कम होने के कारण लोग मजबूरन निजी हॉस्पिटल का रुख करते हैं परंतु उनका भारी भरकम खर्चा उठाना उनके बस में नही है जिसके कारण वो कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और कई वर्षो तक उसकी अदायगी में उनका जीवन नर्क बन जाता है। और सरकारी सुविधा मिलने के साथ नवजात शिशुओं को बेहतर इलाज मिलेगा। और आमजनमानस खुशहाल रहेगा। नगरसेवक रितेश राय की इस पहल को जल्द साकार करने का भरोसा सांसद शिंदे द्वारा दिया गया। इस मांग को लेकर पूरे अंधेरी में रितेश राय की खूब सराहना हो रही है।

गंगा-वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर पर भाजपा में जश्न, कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई

-सुरेश गांधी

वाराणसी। केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा काशी के लिए लगभग 25 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली गंगा एवं वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर सहित मेगा रोड परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न स्थानों पर उत्सव मनाया। महानगर कार्यालय गुलाबबाग और कैंट विधानसभा के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर नृत्य किया, एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। पूरे कार्यक्रम के दौरान 'मोदी जी जिंदाबाद', 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारों से वातावरण गूंजता रहा।

गुलाबबाग स्थित भाजपा महानगर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने कहा कि गंगा एवं वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर काशी के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे शहर की यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राहत मिलेगी तथा आधुनिक अधोसंरचना के साथ काशी की सांस्कृतिक पहचान भी और मजबूत होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति काशीवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया।

वहीं, कैंट विधानसभा के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित समारोह में विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि लगभग 89 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड नेटवर्क, गंगा कॉरिडोर और वरुणा कॉरिडोर के निर्माण से शहर की यातायात व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से शहर तक निर्बाध संपर्क स्थापित होगा, जबकि काशी विश्वनाथ धाम, नमो घाट और अन्य प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक पहुंच पहले की अपेक्षा अधिक आसान होगी। इससे ट्रैफिक जाम में कमी आने के साथ पर्यटन और व्यापार को भी नई गति मिलेगी।

दोनों कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के कटआउट को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की और इसे विकसित काशी के संकल्प को साकार करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया। महानगर कार्यालय के कार्यक्रम में महापौर अशोक तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, प्रेम कपूर, मनीष कपूर, नवीन कपूर, विद्यासागर राय, आत्माविश्वेश्वर, चंद्रशेखर उपाध्याय, निर्मला सिंह पटेल, अखिलेंद्र सिंह 'सनी', प्रमील पांडेय, अजय गुप्ता, रजत जायसवाल, मधुप सिंह, विनोद गुप्ता, वैभव उपाध्याय, प्रमोद यादव 'मुन्ना', अनिल उपाध्याय, राकेश जायसवाल, विनय सिंह, अमित श्रीवास्तव, कुशाग्र श्रीवास्तव, तिरुपति मिश्रा, हीरा यादव, मनोज सोनकर, कुसुम सिंह पटेल, नेहा कक्कड़, पूजा दीक्षित, सपना सिंह, दीपक राय, राजेंद्र सिंह पटेल, शालिनी यादव, विभव सिंह, जेपी सिंह, अनुपम गुप्ता, योगेश वर्मा, साधना वेदांती, साधना पांडेय, डॉ. रचना अग्रवाल, अशोक यादव, पंकज चतुर्वेदी, अवनीश सुयश अग्रवाल, विवेक पांडेय, दीपक सेठ सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक सौरभ श्रीवास्तव, प्रभारी शिवशरण पाठक, डॉ. नंदजी पांडेय, नवरत्न राठी, अभिषेक मिश्रा, अजय प्रताप सिंह, जगन्नाथ ओझा, शिवांग दुबे, पवन शर्मा, अनुराग शर्मा, विपिन ओझा, जयप्रकाश सिंह, सुमित मिश्रा, संदीप केसरी, प्रिंस द्विवेदी, रोहित साहनी, विनोद चौहान, हरिओम, राजमंगल पांडेय, कपिल त्रिपाठी, गौरव पांडेय, लाल बाबू मिश्रा, अजय श्रीवास्तव, कुशाग्र श्रीवास्तव, ऋतिक मिश्रा, अमित पांडेय, चंदन कुमार पाठक, धर्मेश, अक्षय कुमार यादव, मनीष मिश्रा, अरविंद चौधरी और अभिषेक यादव सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।